



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2015/कार्तिक 11, 1937

No. 291]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2015/KARTIKA 11, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों नामशः एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन.गण. एवं कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जांच-परिणाम में सेस्टेट रिमांड मामले के संबंध में।

फा. सं. 14/5/2007-डीजीएडी.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने, घरेलू उद्योग की ओर से नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदनपत्र के परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों नामशः एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन.गण. एवं कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश दिनांक 01 अक्तूबर, 2008 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी के तहत की थी। इस जांच परिणाम के आधार पर चीन जन.गण. और कोरिया आरपी (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ऊपर उल्लिखित रबड़ रसायनों पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 133/2008-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

2. उपर्युक्त अंतिम जांच-परिणाम में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों से अपकृत होकर रबड़ रसायनों में से एक रसायन अर्थात् पीएक्स-13, (6पीपीडी) का निर्यात करने वाले कोरियाई निर्यातक मैसर्स कुम्हों पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी और पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के आयात करने वाले एक भारतीय आयातक मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 01 अक्तूबर, 2008 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा

जारी दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 133/2008-सीमाशुल्क को चुनौती देते हुए और प्रतिवादित अंतिम जांच-परिणाम तथा सीमाशुल्क अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध करते हुए माननीय सीमाशुल्क, उत्पादकर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली (जिसे एतद्पश्चात सेस्टैट या अधिकरण कहा गया है) के समक्ष एक अपील दायर की है।

3. इस जांच में घरेलू उद्योग नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज (एनओसीआईएल) ने भी दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सीमाशुल्क अधिसूचना को चुनौती देते हुए तथा कोरिया आरपी से किए गए निर्यातों पर शुल्क में संशोधन करने/संवृद्धि करने की मांग करते हुए सेस्टैट, प्रधान बैंच, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की है।

4. चीन जन.गण. और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में जारी दिनांक 01.10.2008 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 133/2008-सीमाशुल्क के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ग के अंतर्गत मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी द्वारा दायर अपील संख्या एडी/6,7 और 9/2009-सीयू (डीबी) और नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज और ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य नामक मामले में आवेदन पत्र संख्या एडी/स्टे/1085 और 1449/2009-सील्यू (डीबी); आवेदनपत्र संख्या एडी/विविध/60369, 61349, 60370 और 61348/2009-सीयू (डीबी) में माननीय सेस्टैट ने अपने दिनांक 26.12.2004 को पारित अंतिम आदेश संख्या 54808-54810/2014-सीयू (डीबी) में संबद्ध पक्षकारों की निर्णय दिए जाने के पश्चात् पुनः सुनवाई करने और आदेश की तारीख से अधिमानतः छह माह की अवधि के अंदर अन्य सहबद्ध प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास वापस प्रतिपेक्षित कर दिया।

5. उक्त अपील में सेस्टैट के विचारार्थ संक्षिप्त तथ्य यह था कि अन्य के साथ-साथ, मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी से अन्य के साथ-साथ, पीएक्स-13 (6पीपीडी) के निर्यातों पर प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने यह पाया कि कोरिया आरपी से निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किए जा रहे थे और घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से संचयी रूप से वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी थी। कोरियाई निर्यातक, कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के संबंध में प्राधिकारी ने पीएक्स-13 (6पीपीडी) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के लिए इसकी उत्पादन लागत की संरचना प्रमुख कच्चे माल अर्थात् 4-एडीपीए की, चीन जन.गण. से वास्तविक अधिप्रापण लागत के बजाय, उक्त कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए की थी।

6. निर्यातक कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्तुतिकरण किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 6पीपीडी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपयुक्त ढंग से नहीं किया है; यह कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स 4एडीपीए की खरीद साइनोर्गेकिम, चीन जन.गण. से कर रहा था और यह कि प्राधिकारी ने 4 एडीपीए की वास्तविक लागत को नामंजूर करके, 4 एडीपीए के अधिप्रापण की वास्तविक लागत की अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराने के लिए किसी विधिक प्रावधान के अभाव में, गंभीर गलती की है, क्योंकि कोरिया एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और वह सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 और 8 के उपबंधों के अधीन नहीं है।

7. घरेलू उद्योग के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्तुतिकरण किया कि 4 एडीपीए (6पीपीडी) का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्चा माल) का चीन के साइनोर्गेकिम से अधिप्रापण करने की वास्तविक लागत भरोसेमंद नहीं है क्योंकि इसमें अन्तर्निविष्टियों की अंतर्भूत लागत का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. प्राधिकारी के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया कि चूंकि 6पीपीडी का उत्पादन करने में प्रयोग किए जाने वाले 4पीपीडी को केवल चीन से ही मंगाया जाता था, जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए, कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 4एडीपीए के लिए वास्तविक खरीद कीमत का प्रयोग 6पीपीडी के उत्पादन से जुड़ी लागत को युक्तियुक्त ढंग से परावर्तित नहीं करेगा। प्राधिकारी ने सही ही 6पीपीडी की बिक्री लागत में संशोधन किया है। अपर्याप्त प्रकटन के पहलू के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि अंतिम जांच-परिणाम के पैराग्राफ 58 में और घरेलू उद्योग के पत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 3.09 यूएस डालर प्रति किलोग्राम के रूप में दी गई थी जो सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है। यह भी तर्क दिया गया था कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति को प्रकटन विवरण में समुचित ढंग से दिया गया है।

9. राजस्व विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने इस अधिसूचना का समर्थन इस आधार पर किया कि यह वैध विधिक विचारों पर आधारित था और उन्होंने पैनल रिपोर्टों के उन बिंदुओं का उल्लेख किया कि जहां अंतर्निविष्टियों के अंतर्भूत मूल्य को लेखाओं द्वारा उपयुक्त ढंग से अभिव्यक्त नहीं किया जाता है वहां प्राधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय कीमत अंगीकृत करने के लिए न्यायोचित ठहराया जाता है।

10. उपर्युक्त तर्कों के संदर्भ में, इस अधिकरण ने अपने विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे बनाए :

- (i) क्या प्राधिकारी 4एडीपीए की लागत की अनदेखी करते हुए 6पीपीडी की उत्पादन लागत की संरचना करने में न्याय संगत थे।
- (ii) क्या प्रभावित पक्षकारों को संगत सूचना का प्रकटन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित प्रक्रिया को अपनाया गया है।

11. उपर्युक्त के आलोक में माननीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित अंतिम आदेश पारित किए :

जांच-परिणाम एवं आदेश

20. उपर्युक्त के मद्देनजर हमारा यह विचार है कि प्राधिकारी ने न्यायोचित ढंग से ही साइनोर्गेमिक की 4एडीपीए की कीमतों को अस्वीकार कर दिया और सामान्य मूल्य की संरचना 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करने का विकल्प अपनाया। तथापि, 4एडीपीए की चीन की कीमतों को न्यायोचित ढंग से नामंजूर करके और सामान्य मूल्य की संरचना 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करने का विकल्प अपनाकर प्राधिकारी के लिए उसका यथोचित प्रकटन करना और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साक्ष्यों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से सूचना/टिप्पणियां मंगाना आवश्यक था। हम यह उपपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जर्मनी से भारत को 4एडीपीए की आयात कीमतों के साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। परंतु प्राधिकारी ने अंतिम जांच-परिणाम रिकार्ड करने से पहले इन साक्ष्यों की स्वीकार्यता/उपयुक्तता के संबंध में अपनी टिप्पणियां करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान नहीं किया। इस सीमा तक, प्राधिकारी ने न्यायोचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और कोरियाई निर्यातकों के अधिकारों का विपरीत ढंग से प्रभाव डाला। हमें घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण में भी अच्छाई नजर आ रही है कि निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है जिससे कि वह उन पर सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाते। पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन [2012 (263) 481 (एससीसी)] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित का प्रतिपादन किया है :

"58. इस प्रकार, यह सुस्थापित है कि जब तक कोई सांविधिक प्रावधान, या तो विशेष रूप से अथवा आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का अपवर्जन न करता हो तब तक, क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय विधायी अधिदेशों की अनदेखी नहीं करेगा, कोई आदेश किए जाने से पहले सुनवाई किए जाने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने की जरूरत को सामान्यतः उस संविधि के उपबंधों में पढ़ा जाता है, विशेषकर तब तक कि उस आदेश के विपरीत सिविल परिणाम हो, जिनमें स्पष्टतः पीड़ित पक्षकार के लिए संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन और वास्तविक वंचन शामिल हो। इस सिद्धांत को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना अच्छा माना जाता है कि क्या किसी सांविधिक निकाय या न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्ति प्रशासनिक है अथवा न्यायिक कल्प। यह समान रूप से एक चिसीपिटी सोच है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को न तो जकड़ कर रखा जा सकता है और न ही यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक सामान्य सिद्धांत है। निःसंदेह रूप से, उक्त सिद्धांत के कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न कि क्या इस सिद्धांत को शक्ति प्रदान करने के उपबंधों की आधारभूत स्कीम और अभिव्यक्त भाषा; प्रदत्त शक्ति की प्रकृति और उस प्रयोजन जिसके लिए वह शक्ति प्रदान की गई है और उस शक्ति का प्रयोग करने के अंतिम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुप्रयोग करना चाहिए या नहीं। इन मामलों पर विचार करने के पश्चात् ही उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग के प्रश्न का समुचित रूप से निर्धारण किया जा सकता है। [देखें भारत संघ बनाम कर्नल जे. एन. सिंह एवं अन्य (1970) 2 एससीसी 458]।

59. ऊपर नोट की गई विधिक स्थिति और वर्ष 1995 की नियमावली के नियम 6 में विहित विस्तृत प्रक्रिया, जिसका जांच का आयोजन करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाना एक बाध्यता है, के आलोक में हम आश्चर्य हैं कि प्राकृतिक न्याय का अनुपालन करने के कर्तव्य का उक्त नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में स्पष्ट उल्लेख है।

21. इसलिए हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निदेश देते हैं कि वह प्राधिकारी द्वारा 4एडीपीए की अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की गई क्रियापद्धति का प्रकटन करें। निर्दिष्ट प्राधिकारी पक्षकारों को निर्णय पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे और 6पीपीडी के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण उपर्युक्त प्रेक्षणों, जहां तक उनका संबंध कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स से है, के आलोक में करेंगे। प्रतिवादी घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हो, को इस निर्णय पश्चात् सुनवाई में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार अंतिम जांच-परिणाम में किए गए किसी भी प्रकार के संशोधनों पर सरकार द्वारा प्रतिवादित पाटनरोधी शुल्क में सुधार करने के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। इस कार्रवाई को यथाशीघ्र, अधिमानतः, इस आदेश की तारीख से 6 माह के अंदर, पूरा किया जाएगा। इस बीच यथास्थिति कायम रखी जाएगी।

ख. प्रक्रिया

12. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

- क. माननीय सेस्टैट के आदेश के अनुपालन में प्राधिकारी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के ई-मेल के तहत हितबद्ध पक्षकारों को भारत को जर्मनी से 4एडीपीए कच्चे माल की उन आयात कीमतों की जानकारी प्रेषित कर दी जो घरेलू उद्योग ने साक्ष्य के रूप में रिकार्ड करवाई थी और जिसे प्राधिकारी ने कोरिया आरपी के सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए अपनाया था।
- ख. माननीय सेस्टैट के आदेश के अनुपालन में प्राधिकारी ने अपने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के ई-मेल के तहत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन करने की क्रिया प्रणाली की भी जानकारी प्रदान कराई।
- ग. प्राधिकारी ने दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को आयोजित मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इस मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया : नेशनल आर्गेनिक कैमिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनओसीआईएल), घरेलू उद्योग, मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी (निर्यातक) और ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)।
- घ. मौखिक सुनवाई के समय अपने विचार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें और उन्हें विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की प्रत्युक्तियां भी दायर करने का अवसर प्रदान किया गया। मौखिक सुनवाई के पश्चात् निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तुतिकरण दायर किए :

- एनओसीआईएल - घरेलू उद्योग
- मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कोरिया आरपी और
- मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

- ङ. प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात् आयोजित मौखिक सुनवाई में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों की तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में विस्तार से जांच की गई और प्राधिकारी द्वारा इस वर्तमान जांच में इस पर संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया।
- च. मौखिक सुनवाई के बाद दिनांक 03.08.2015 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया। तथापि, आकस्मिक प्रशासनिक परिवर्तन के कारण एक नए अधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया। इससे यह आवश्यक हो गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 07.01.2011 की वर्ष 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में डिबीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नवीन सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाए। इसलिए, नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2015 को एक नवीन मौखिक सुनवाई का आयोजन कराया गया। इस सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण करें। इस द्वितीय मौखिक सुनवाई के पश्चात् निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुतिकरण किए :

- एनओसीआईएल घरेलू उद्योग
- मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कोरिया आरपी और
- मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

- छ. इस जांच के अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच-परिणाम का आधार बनेगा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 06.10.2015 को जारी किया गया। द्वितीय प्रकटन विवरण के पश्चात् घरेलू उद्योग और उन्हीं हितबद्ध पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतिकरण किया गया जिस पर इस जांच में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया।
- ज. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और नियमावली के अंतर्गत गुणों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उस पर वैसे ही विचार किया गया।
- झ. प्राधिकारी ने इस जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 53.69/-रुपए = 1 यूएस डालर अपनाया है।

ग. निर्णय पश्चात् मौखिक सुनवाई के पश्चात् किए गए प्रस्तुतिकरण**ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण**

13. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए :

- क. सेस्टैट ने 4एडीपीए की कीमतों को अस्वीकार करने और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य को अपनाए जाने की परिपुष्टि कर दी है। अब यह मुद्दा वर्तमान निर्णय पश्चात् सुनवाई के दायरे से परे है। वर्तमान निर्णय पश्चात् क्रियाविधि का दायरा केवल अंतर्राष्ट्रीय कीमत और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का प्रकटन करना है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी सेस्टैट द्वारा किए गए प्रेक्षणों के आलोक में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं।
- ख. घरेलू उद्योग को केकेपीसी की उत्पादन लागत की संरचना करने के संबंध में निर्धारण के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति, जिसमें सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियां भी शामिल हैं, से संबंधित कोई भी प्रकटन प्रदान नहीं कराया गया है। केकेपीसी को जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट और उस सत्यापन रिपोर्ट पर केकेपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां अपनाई गई क्रियापद्धति और निर्धारण किए गए पाटन मार्जिन का आधार है और इसलिए इसका प्रकटन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और घरेलू उद्योग के लिए संगत है। घरेलू उद्योग ने उसका प्रकटन किए जाने की मांग की है।
- ग. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए व्याज लागत की संगणना करने के तरीके का भी घरेलू उद्योग को प्रकटन नहीं किया गया है, इसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि उस व्याज आय को, जो इस विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है, उसे व्याज व्यय के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है।
- घ. सामान्यतः स्टीम एक विपणन योग्य वस्तु नहीं है और इसलिए इसकी लागत का निर्धारण हमेशा विवादास्पद रहा है। इसलिए, अन्य उत्पाद के लिए स्टीम के प्रयोग से राष्ट्रीय आय द्वारा उत्पादन लागत में कमी करने की अनुमति नहीं है।
- ङ. कंपनी ने एसजीए व्ययों का दावा किया है, जो सच्चे अर्थों में टर्न-ओवर (कारोबार) आधार पर नहीं है। कंपनी द्वारा अनेकों समायोजन किए जाते हैं, जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में स्वीकार नहीं किया है। यह समायोजन सकल तौर पर कंपनी की बहुत सी सूचनाओं का प्राधिकारी से प्रतिच्छाया कर रही है।
- च. यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने अपनी ग्राही अंतर्निविष्टियों की कीमत किस तरह निर्धारित की है। ग्राही रूप से उत्पादित कोई अंतर्निविष्टि को प्रचलित बाजार दरों पर प्रभावरित किया जाना चाहिए।
- छ. यद्यपि, 4एडीपीए की संरचना में सीमाशुल्क (आयात) को शामिल नहीं किया गया है फिर भी अंतर्निविष्टि प्रतिअदायगी के प्रति ऋणात्मक कमी (संवर्धन) किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने निर्यात कीमत में सीमाशुल्क लाभ की अनुमति, उसको उत्पादन लागत में जोड़े बिना दी है।
- ज. केकेपीसी की उत्पादन लागत की संरचना करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को केकेपीसी द्वारा उपगत किए गए निम्नलिखित व्ययों को शामिल करना अपेक्षित होता है – (i) पत्तन व्यय (ii) निकासी व्यय (iii) कास्टम्स ड्यूटी और (iv) कोरियाई पत्तन से कारखाने तक अंतर्देशीय भाड़ा।
- झ. यद्यपि, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए अपनाई गई "क्रियापद्धति" का प्रकटन किया है, फिर भी सेस्टैट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना का अभी भी प्रकटन नहीं किया है।
- ञ. कुम्हो द्वारा दावाकृत उत्पादन लागत का कम आकलन किया गया और उसकी स्टीम, व्याज लागत, एसजीए व्यय, ग्राही अंतर्निविष्टियों आदि की लागत के संबंध में उसकी जांच करना अपेक्षित है।
- ट. यथार्थता एवं यथेष्टता से संबंधित घरेलू उद्योग के दावे का कोरियाई निर्यातक, भारतीय आयातकों, इस विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं द्वारा कभी भी विरोध नहीं किया गया है। इन हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां केवल उपयुक्तता तक ही सीमित थीं। इसलिए यथार्थता एवं यथेष्टता से संबंधित प्रश्न अब चर्चा के लिए खुला नहीं है।
- ठ. पर्याप्त समय और अवसर होने के बावजूद न तो कोरियाई निर्यातक ने और न ही भारतीय आयातक ने घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2008 में प्रस्तुत 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साक्ष्य का विरोध करने के लिए साक्ष्य का कोई भी बिंदु प्रस्तुत नहीं किया है। निर्यातक या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अभिवर्तित किए गए किसी वैकल्पिक साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी को उनके रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारण करना अपेक्षित होता है।
- ड. घरेलू उद्योग ने 3.09 यूएस डालर की कीमत का दावा किया है और यह प्रकटन किया है कि यह आईबीआईएस आंकड़ों पर आधारित है। यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों को यह दावा करने का अधिकार है कि प्राधिकारी को अपने रिकार्डों को तथा अपने रिकार्डों के अनुरूप उपभोग कीमत को अपनाना चाहिए, तथापि इन हितबद्ध पक्षकारों की प्राधिकारी के समक्ष यह दावा करने की बाध्यता थी कि 3.09 यूएस डालर के आंकड़े अथवा वह स्रोत जिसके आधार पर यह आंकड़े अपनाए थे उपयुक्त नहीं हैं।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों ने न तो सौदावार सूचना की मांग की है और न ही यह कहा है कि आईबीआईएस पर आधारित दावा किए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकार इस निर्णय पश्चात् सुनवाई को तथ्य प्राप्त करने वाली जांच वह कार्य जो मूल जांच के समय प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आंकड़ों के सार्ट आउट करने के लिए किसी क्रियापद्धति को अपनाना अपेक्षित नहीं है। 4एपीडीए का आयात ज्ञात नामों से किया जाता है और उन सभी सौदों, जिनमें विवरण का उल्लेख किया गया है, पर विचार किया जाना चाहिए।
- ण. प्राधिकारी पर भारतीय राजदूतावासों अथवा विभिन्न पत्तनों से सूचना प्राप्त करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जांच में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वे प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान कराएं। प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और प्रस्तुतिकरणों के आधार पर निर्धारण करें।

- त. प्राधिकारी ने विगत में कई मामलों में डीजीसीआईएंडएस के अलावा कई निजी एजेंसियों से अवाप्त आयात आंकड़ों को अपनाया है। विगत में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों की उपेक्षा करके आईबीआईएस अथवा अन्य गौण स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को अपनाया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में अपनाए गए आईबीआईएस आंकड़ों पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्राधिकारी द्वारा इसका साक्ष्य प्रदान नहीं कराया जाता है।
- थ. निर्यातक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भुगतान की शर्तों, सुपुर्दगी की शर्तों, भाड़ा आदि जैसे कारकों का अभिव्यक्ति एवं सीमा उल्लेख करे जो समायोजन करने के प्रयोजनार्थ कीमतों को प्रभावित करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि इस तरह के समायोजन केवल वही अनुमेय हैं जहां निर्यातक यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान करता है जो कीमतों पर इन कारकों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, कोरिया से फैक्टरी तक पत्तन व्यय, सीमाशुल्क, अंतर्देशीय भाड़ा के कारण किए गए समायोजनों को करने की जरूरत है।
- द. सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली और इस नियमावली का क्रियान्वयन करने वाले सीमाशुल्क विभाग की विशेष मूल्यांकन शाखा यदि उन्हें यह ज्ञात होता है कि संबंधों के कारण कीमतें प्रभावित हुई हैं तो घोषित मूल्यों को नैतिक रूप से नामंजूर कर देती है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जिन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, उन पर इस स्तर पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
- ध. प्राधिकारी को संगत अवधि के दौरान विभिन्न गंतव्यों को मौजूद भाड़ा दरों को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है भाड़ा दरें अधिकांशतः केवल दूरी पर आधारित न होकर विभिन्न पत्तनों के बीच व्यापार की मात्रा पर निर्भर करता है।
- न. निर्यातक को कोरिया में 6.5 प्रतिशत का पत्तन व्यय और सीमा शुल्क तथा कोरियाई पत्तन से फैक्टरी तक अंतःस्थलीय भाड़े पर व्यय उपगत करना पड़ता है। प्राधिकारी को कोरिया से उत्पाद का निर्यात करने वाले निर्यातक द्वारा दावा किए गए अंतःस्थलीय भाड़े पर विचार करना चाहिए।
- प. यदि 4एडीपीए की कीमतों को अपनाया जाता है तो विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। प्रक्रिया में अभिकथित अंतर का अधिकाधिक उत्पादन लागत पर अंतर हो सकता है। कच्चे माल की विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में ऐसा कोई भी समायोजन नहीं किया गया है, जबकि संभावित उत्पाद अथवा उस उत्पाद के लिए कच्चा माल विगत मामले में समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा हो।
- फ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पीएमसी रबड़ कैमिकल्स लिमिटेड भी कच्चे माल की खरीद चीन से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कर रही है, यह मुद्रा सेस्टैट निर्णय के पैरा 20 के आलोक में यथापठित निर्णय पश्चात् सुनवाई के दायरे से परे हैं।
- व. इस तर्क के लिए कोई भी आधार नहीं है कि यदि मात्रा अधिक होगी तो कीमत कम होगी। वास्तव में यह नैमित्तिक व्यावसायिक स्थिति है कि संविदा के अंतर्गत कीमत स्थल खरीद (और उसके विपरीत) कीमत की तुलना में अधिक हो सकती है।
- भ. हितबद्ध पक्षकारों के पास प्राधिकारी को दस्तावेज और साक्ष्य प्रदापन करके सहयोग करने का पूरा अवसर था और वे मूल जांच के समय प्राधिकारी के समक्ष दावा कर सकते थे। हितबद्ध पक्षकार निर्णय पश्चात् सुनवाई की इस स्थिति को कम करके तथ्य प्राप्त करने वाली जांच प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
- म. जहां तक विनिमय दरों में अंतर होने के तर्क का संबंध है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, और घरेलू उद्योग ने इस दावे को सत्यापित करने के लिए प्राधिकारी को औसत विनिमय दर तालिका प्रदान कराई है।
- य. घरेलू उद्योग के दावे को खंडित करने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों का सेस्टैट आदेश के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं है।
- क. इस जांच को पूरा करने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि प्रतिवादी अधिसूचना के अनुसरण में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मियाद काफी समय पहले ही पूरी हो गई है और प्राधिकारी द्वारा आयोजित निर्णायक समीक्षा के परिणामस्वरूप अधिरोपित नवीन शुल्क लागू है।
- ख. न्यायाधिकरण द्वारा एक बार यह धारित कर दिए जाने पर कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करेंगे, तो इसका आशय यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से उसके सभी संगत पहलुओं पर विचार करना अपेक्षित है।
- ग. अंगीकृत कीमत सीआईएफ कीमत थी और इसलिए उसका संदर्भ सभी पक्षकारों को यह स्पष्ट कर देता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीआईएफ आयात कीमत को अंगीकृत किया है।
- घ. प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत कीमत में भारत में संदेय सीमा शुल्क शामिल नहीं है और इसलिए, इसमें पुनः कमी नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का दावा भारत में उपभोग कीमतों के आधार पर नहीं किया है। प्राधिकारी इस खपत कीमत को अपना सकते हैं और 4एडीपीए की लागत में सीमाशुल्क और इसके आयात से जुड़े सभी व्यय को जोड़ सकते हैं। प्राधिकारी से इस उपभोग कीमत पर विचार करने और तदनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता है।
- ङ. भारत को जर्मनी से कीमतों पर संबंधों का कोई प्रभाव नहीं है। वास्तव में व्यवस्था में दो संबद्ध पक्षकारों के बीच हो रहे सौदों में वस्तु का आकलन करने का स्पष्ट प्रावधान है। यद्यपि यह प्रावधान कोरिया में भी मौजूद है, तथापि साइनोर्गेकिम और केपीसी के बीच हो रहे सौदे इस संवीक्षा के अध्यक्षीन इस तथ्य पर विचार करते हुए नहीं रहेंगे कि उनके बीच सीमाशुल्क

विधि के अधीन संबद्ध पक्षकार के आशय के अंतर्गत कोई संबंध नहीं है। ऐसा होते हुए भी याचिकाकर्ता ने 4एडीपीए की उत्पादन लागत पर विचार करने का वैकल्पिक दावा याचिकाकर्ता द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार किया है।

- च. सीमाशुल्क में रिपोर्ट की गई कीमतों में पत्तन व्ययों को कभी शामिल नहीं किया जाता है।
- छ. वास्तव में सीमाशुल्क आंकड़ों पर स्वतंत्र आंकड़ों के रूप में विचार किया जाता है। वस्तुतः, डब्ल्यूटीओ करार में भी यह प्रावधान है कि प्राधिकारी सीमाशुल्क आंकड़ों पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में विचार कर सकते हैं। इसलिए, उसको पुनः सत्यापित किए जाने की कोई जरूरत नहीं है।
- ज. परिकलनों युक्त एक्सेल शीट प्रदान कराने की कोई विधिक जरूरत नहीं है।

ग.2. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

14. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- क. सेस्टैट के आदेश के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सैनडिस्क इंटरनेशनल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य की रिट याचिका संख्या 744/2015 में रद्द कर दिया गया है; जिसमें सेस्टैट के इस आदेश को माननीय न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया परंतु न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया और यह उद्धोषित किया कि प्राकृतिक न्याय के सकल उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, अंतिम जांच परिणाम न तो कायम रखी जा सकती है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस रिमांड की जा सकती है।
- ख. गौण स्रोत से साक्ष्य संग्रहित करने के संबंध में प्राधिकारी का दायित्व पूरा नहीं होता है। सेस्टैट के निर्णय के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी से उपयुक्त प्रकटन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साक्ष्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मंगाने के लिए कहा गया था।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा 4एडीपीए के आयात आंकड़े निम्नलिखित समस्या सृजित कर रहे हैं :

- (i) घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी को अपरिष्कृत आंकड़े कभी भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे और ऐसे आंकड़े न होने पर प्राधिकारी सूचना की यथार्थता और यथेष्टता का सत्यापन नहीं कर पाए।
- (ii) अपरिष्कृत आंकड़ों के साथ-साथ प्रतिवादियों को परिष्कृत आंकड़ों का प्रकटन भी किया जाना चाहिए।
- (iii) अपरिष्कृत आंकड़ों सार्वजनिक करने के लिए अपनाई गई क्रियाप्रणाली प्रदान नहीं कराई गई।
- (iv) चूंकि प्राधिकारी ने 4एडीपीए की कीमतों को बिना किसी सत्यापन के अपनाया है, इसलिए समस्त प्रयोजन व्यर्थ हो गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ एडीए के अनुच्छेद 6.8 का भी उल्लंघन हुआ है।
- (v) प्रतिवादियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने विगत में कभी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य तथ्यों/आंकड़ों को सत्यापन किए बिना और उनकी पुष्टि किए बिना कमीशन पर भरोसा किया है और अपनाया है।
- (vi) प्राधिकारी को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसने विभिन्न पत्तनों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों, डीजीसीआईएस और संपूर्ण विश्व में भारतीय राजदूतावासों को 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सुनिश्चयन करने के लिए लिखा है।

- घ. प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह जांच आयोजित करें और घरेलू उद्योग का यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह आंशिक रूप से जांच आयोजित करे। निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से आवश्यक है कि वह प्रतिवादियों को यदि इसे घरेलू उद्योग द्वारा अवाप्त कराया जाता है तो प्रतिवादियों को अपरिष्कृत आयात आंकड़े उपलब्ध कराएं। एक ऐसे परिदृश्य में जहां कच्चे माल को घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया हो तब यह और भी अधिक आदेशित हो जाता है कि प्राधिकारी इन आंकड़ों को प्राप्त करे और इन आंकड़ों की यथार्थता की स्वतंत्र रूप से समानता करे।
- ङ. विगत में प्राधिकारी ने आंकड़ों में त्रुटि के कारण उन्हें नामंजूर कर दिया था, जब ये आंकड़े आईवीआईएस/साइबेक्स/इन्फोडाइव जैसी गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा उन्हें प्राप्त किया गया और उनमें त्रुटि पाई गई और उसकी अनदेखी कर दी। उदाहरण के लिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव मामला है।
- च. यह आवश्यक है कि हितबद्ध पक्षकारों को यह सम्पुष्टि करने के लिए आयात सांख्यिकी प्रदान कराया जाना चाहिए कि :

- (क) आयात सांख्यिकी में केवल 4एडीपीए शामिल है।
- (ख) आयात की मात्रा की जांच करें जिससे कि बहुत अधिक अथवा निम्न मात्रा पर विचार न किया जाए।
- (ग) भुगतान की शर्तों और सुपुर्दगी की शर्तों का सत्यापन किया जाए और तदनुसार उसका समायोजन किया जाए।
- (घ) भाड़ा तत्व की जांच किया जाना अपेक्षित होता है।

- छ. मेरी सर्वोत्तम समझ यह है कि उस समय पर लैनेक्सेस जर्मनी ही 4एडीपीए का एकमात्र उत्पादक था और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत स्थित उसकी संबद्ध कंपनी ने भारत में 4एडीपीए का आयात किया है। प्राधिकारी को निम्नलिखित की जांच करना अपेक्षित है :
- (i) इन कीमतों को बाजार कीमतों का प्रदर्शन करने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह सौदे संबद्ध पक्षकारों के बीच हुए थे। अन्यथा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। सीमाशुल्क प्राधिकारी भी कोई संदेह प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इन उच्च मूल्यों वाले सौदों से अधिक सीमाशुल्क प्राप्त हो रहा है।
 - (ii) जर्मनी, एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश, से भारत को सीआईएफ कीमतें साइनोर्गेकिम से केपीसी को 4एडीपीए की कीमत आसानी से स्थानापन्न कीमत नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें जर्मनी से भारत को भाड़ा शामिल होता है, न कि चीन से कोरिया को क्योंकि एक दूसरे के बीच में दूसरी का अंतर 15 गुने से भी अधिक है।
 - (iii) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में भाड़े का समायोजन किया है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाड़े का समायोजन करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
 - (iv) साइनोर्गेकिम और फ्लेक्सिस दोनों द्वारा अपनाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए, 4एडीपीए का उत्पादन करने की लागत में भारी अंतर होगा। प्राधिकारी को चाहिए कि वह उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के आधार पर यथोचित समायोजन करें।
- ज. यह स्पष्ट है कि इस सार का आधार घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सौदेवार वह आयात सांख्यिकी जिससे यह सार तैयार किया गया है निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान भी नहीं कराई गई थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक ऐसे असाक्ष्यांकित सार पर भरोसा किया और उसे साक्ष्य के रूप में अपनाया तथा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिया।
- झ. यह भी स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कभी कोई ऐसा साक्ष्य/एसे आंकड़े नहीं रहे जिससे यह सिद्ध हो जाता कि वह सौदेवार मूल्य क्या है जिस पर 4एडीपीए को अधिप्राप्त किया और वह सौदेवार मूल्य न्यूनतर अथवा अविश्वसनीय था।
- ञ. इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सार के रूप में प्रदान कराए गए आंकड़ों का किसी भी तरह से कभी कोई वैधीकरण/सत्यापन नहीं किया।
- ट. यदि यह प्रकल्पना की जाती है कि चीन जन.गण. से निर्यात कीमत हमेशा कम ही रहती है और उसका सौदा मूल्य भरोसेमंद नहीं है क्योंकि चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए हर हाल में चीन से भारत को आयातित वस्तु का आकलन करते वक्त सौदा मूल्य को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए और उसे कर निर्धार्य योग्य मूल्य पर बनाने के लिए लोड/संवर्धित किया जाना चाहिए और उस पर उच्चतर शुल्क लगाया जाना चाहिए। तथापि, यह कार्रवाई केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित होगी और इसका विधि न्यायालय में कोई आधार नहीं होगा।
- ठ. निर्दिष्ट प्रतिधकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह 4एडीपीए की कीमतों के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराएं जिनका प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव किया जा सके।
- ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह संबद्ध जांच से अन्य उन उदाहरणों का भी प्रकटन करें जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल भरोसा ही किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों/आंकड़ों को बिना कोई सत्यापन किए एवं उन तथ्यों/आंकड़ों का बिना कोई साक्ष्यांकन किए अपनाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों/आंकड़ों पर भरोसा केवल तभी करें और उन्हें केवल तभी अपनाएं जब वह उसका सत्यापन कर ले और उनका साक्ष्यांकन कर लें।
- ढ. यदि पीएमसी रबड़ कैमिकल्स लिमिटेड भी कच्चे माल की खरीद चीन से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कर रहा है तो केपीसी द्वारा उसकी आयात कीमतों को स्वीकार न करना न्यायोचित नहीं है।
- ण. प्राधिकारी को चीन मूल की कीमतों का अंगीकरण केपीसी अथवा साइनोर्गेकिम को असहबद्ध उत्पादों से पीएमसी आयात कीमत के संबंध में सीमाशुल्क (कस्टम्स) से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही करना चाहिए।
- त. केपीसी ने जांच की अवधि के दौरान साइनोर्गेकिम से भारी मात्रा में 4एडीपीए की खरीद की है और तदनुसार प्राधिकारी को चाहिए कि वह मात्रा डिस्काउंट के लिए समायोजन प्रदान कराएं।
- थ. (i) चीन से भारत को 4एडीपीए की आयात कीमत (ii) जर्मनी से भारत को 4एडीपीए की आयात कीमत और (iii) भारत को औसत आयात कीमत के लिए अलग-अलग विनिमय दर अपनाई गई है। अपनाई गई विनिमय दर समान होनी चाहिए। इससे अपरिष्कृत आंकड़े प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश पड़ता है।
- द. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की बिक्रियों पर अर्जित लाभ पर समग्र रूप से विचार किया है जिसमें निर्यात बिक्रियों से अर्जित लाभ को भी शामिल किया गया है। प्राधिकारी को चाहिए कि वे केवल घरेलू बिक्रियों पर लाभ मार्जिन पर विचार करें अथवा संगत परम्परा के अनुसार 5 प्रतिशत लाभ मार्जिन पर विचार करें जैसा कि निर्णायक समीक्षा में अपनाया गया है।
- ध. सेस्टैट ने वास्तव में यह धारित किया है कि प्राधिकारी 4एडीपीए की कीमतों को अस्वीकार करते वक्त सही थे परंतु वह निर्णय केवल इस कल्पना के आधार पर किया गया था कि एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कीमत विद्यमान है।

- न. सेस्टेट ने यह धारित किया है कि प्राधिकारी साइनोर्गेकिम से 4एडीपीए की कीमतों को नामंजूर करने और सामान्य मूल्य की संरचना 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करने का विकल्प लेते समय सही थे। तथापि, घरेलू उद्योग ने वृष्टिपूर्ण ढंग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्राधिकारी 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अपनाए जाने और साइनोर्गेकिम से 4एडीपीए की कीमतों का अस्वीकार किए जाने की यथार्थता पर विचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेस्टेट ने यह निष्प्रय भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की मौजूदगी की प्रकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालकर किया है।
- प. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कीमत प्राथमिकतः भरोसेमंद नहीं है क्योंकि इस कीमत में लैनेक्सेस जर्मनी और लैनेक्सेस भारत, जो सहबद्ध पक्षकार है, के बीच हुई बिक्रियां शामिल हैं। अतः, यह कीमत ऐसी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके और उसे अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 4 एडीपीए की कोई भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय कीमत उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी को चाहिए कि वह साइनोर्गेकिम से 4एडीपीए की कीमतें अपनाएं।
- फ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए क्रिया पद्धति के प्रकटन के लिए वही प्रक्रिया अपनाना चाहिए जो क्रिया पद्धति उन्होंने निर्यातकों की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई है। सेस्टेट के आदेश में कहीं भी यह अधिदेश नहीं दिया गया है कि केपीसी के व्यक्तिगत लागत निर्धारण तत्व का प्रकटन करना चाहिए। यह सूचना प्रकृति से ही गोपनीय है और इसका प्रकटन करना सेस्टेट आदेश के दायरे से बाहर है।
- ब. अपनी पिछली सभी जांचों में प्राधिकारी ने केवल निर्यातकों के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के सिद्धांत पर ही प्रकाश डाला है; उन्होंने इस गैर-क्षतिकारी कीमत की संगणना करते वक्त परिकलन के प्रत्येक तत्व की अभिव्यक्ति नहीं की है। इसी तरह सामान्य मूल्य की संगणना करते समय केवल सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के सिद्धांत का ही प्रकटन किया जाना चाहिए न कि परिकलन के प्रत्येक सिद्धांत की।
- भ. प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रकटन करें और प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई इस कीमत की उपयुक्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करें और उन पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन को अंतिम रूप देने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का प्रकटन करें और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनः निर्धारण करें।
- म. प्राधिकारी को चाहिए कि वह सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की गई क्रियापद्धति का प्रकटन करें और उनसे केपीसी के व्यक्तिगत कीमत निर्धारण तत्व का प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि यह गोपनीय प्रकृति का होता है और इस सूचना का प्रकटन करना सेस्टेट के आदेश तथा पाटनरोधी नियमावली के दायरे से बाहर है। प्राधिकारी को चाहिए कि वह किसी एक जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्रकटन का एक समान मानक अपनाएं।
- य. केपीसी की सत्यापन रिपोर्टें और सत्यापन प्रदर्श गोपनीय सूचनाएं हैं और उनका घरेलू उद्योग को प्रकटन नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग नियम 16 के छद्म आश्रय के अंतर्गत केपीसी की गोपनीय सूचनाओं तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और यदि इन सत्यापन रिपोर्टों एवं इन सत्यापन प्रदर्शों का प्रकटन कर दिया जाता है तो ऐसा दोनों ही पक्षकारों के लिए किया जाना चाहिए।
- कक. प्राधिकारी ने केपीसी की लागत निर्धारण सूचना का स्थल सत्यापन करके सत्यापन किया है और वह इस सूचना की यथातथ्यता से पूर्णतः संतुष्ट हैं।
- खख. किसी ऐसे विशिष्ट उदाहरण को अभिज्ञात किए बिना जहां ब्याज लागत से संबंधित आरोप वास्तव में घटित हुआ है, प्रतिवादीगण उस पर सार्थक टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं।
- गग. घरेलू उद्योग से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि किस लेखाकरण नियम के अंतर्गत ग्राही अंतर्निविष्टियों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया गया है। उत्पादन लागत का निर्धारण करते समय निर्यातक द्वारा उपगत की गई वास्तविक लागत का सुनिश्चयन किया जाना चाहिए।
- घघ. माननीय सेस्टेट ने शुल्क प्रतिअदायगी के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण को नोट किया है परंतु इस विषय पर उसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है जो यह दर्शाता है कि माननीय सेस्टेट यह महसूस करता है कि इस पहलू पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।
- ड.ड. माननीय सेस्टेट ने अपने आदेश में यह नोट किया है कि "9. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अपील के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि विचार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोरिया में 6पीपीडी की आयात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि, जिस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी उसका अवसान पहले ही हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस स्तर पर इस मुद्दे पर अधिक बल नहीं दिया।"
- चच. वह कारण जिस पर प्रतिवादियों ने 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का विरोध नहीं किया, यह है कि मूल जांच के दौरान केपीसी द्वारा सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई 4एडीपीए की कीमतों के संबंध में प्रतिवादियों को कभी कोई भी प्रकटन नहीं किया गया और इसलिए उस संबंध में टिप्पणी करने का कोई मौका ही नहीं था और इसी कारण से प्रतिवादियों ने सेस्टेट में अपील कर आश्रय लिया।
- छछ. केपीसी ने प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से यथासत्यापित सभी सूचना का यथातथ्य प्रकटन किया है और प्राधिकारी उसकी यथार्थता से संतुष्ट थे। चूंकि प्राधिकारी इस प्रतिवादी के लेखाकरण रिकार्ड से संतुष्ट थे, इसलिए इस मुद्दे को उठाने का घरेलू उद्योग का प्रयास सही ही अस्वीकार कर दिया गया है।

- क. माननीय सेस्टेट ने यह निदेश दिया था कि रिमांड की कार्यवाही आदेश की तारीख से छह महीने के अंदर पूरी की जाए। तथापि, सेस्टेट के आदेश की तारीख से छह माह से अधिक का समय गुजर गया है, और प्राधिकारी ने रिमांड की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं की है। सेस्टेट के आदेश में प्रयोग किया शब्द "अधिमानतः" का अभिप्राय यह नहीं है कि इसकी कार्यवाही "अधिमानतः" छह माह की समाप्ति पर प्रारंभ की जाएगी।
- ख. वस्तु का पाटन नहीं हो रहा था, और इसके परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती समीक्षाओं में किसी तरह के शुल्क की निरंतरता बनाए रखना अथवा उसके समय में विस्तार करना अवैध है। इसलिए, इस कार्यवाही में केपीसी के लिए पाटन मार्जिन का समुचित निर्धारण करने में दूरगामी परिणाम होंगे।
- ग. न्यायाधिकरण में यह मामला केवल इस सीमा तक रिमांड किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल उन आंतरिक कीमतों का प्रकटन करेंगे जिनको केपीसी द्वारा 4एडीपीए की वास्तविक अधिप्रापण कीमतों से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और फिर प्रतिवादी (केपीसी) की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् पाटनमार्जिन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
- घ. जहां तक मालभाग, प्रहस्तन प्रभारों और सीमा शुल्क में अन्य समायोजन किए जाने का संबंध है, यह समायोजन वृत्तिपूर्ण ढंग से किए गए हैं क्योंकि :

- (i) चूंकि आवेदक घरेलू उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में कभी यह मुद्दा नहीं उठाया है, इसलिए उन्हें रिमांड कार्यवाही में यह मुद्दा उठाने से बहिष्कृत किया जाता है, यद्यपि आवेदक घरेलू उत्पादक उस बिंदु पर सीमा शुल्क शामिल करने में असफल रहे थे।
- (ii) यद्यपि अपील में शुल्क प्रतिअदायगी का मुद्दा नहीं उठाया है इसलिए इस रिमांड कार्यवाही में इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिमांड कार्यवाही में इस मुद्दे की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। केपीसी को उस बदतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जहां पर वे अपील दायर करने से पहले थे।
- (iv) आवेदक घरेलू उत्पादक, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रदान कराई और जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनाया है, को इन खर्चों (भारत में संदेय 15 प्रतिशत सीमाशुल्क तथा माल भाड़ा एवं प्रहस्तन प्रभार) को जोड़ना चाहिए और इसलिए, पहले तो इन व्ययों को घटाना अपेक्षित है और फिर केवल तुलनीय व्यय को ही जोड़ना चाहिए।

- ङ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने शब्द "सीआईएफ" का प्रयोग पहली बार अपने प्रथम प्रकटन विवरण में किया था क्योंकि यह शब्द उस अंतिम शब्द परिणाम में नहीं था जिसे पुनः रिमांड किया गया। इसे दावाकृत उतराई मूल्य में सीमाशुल्क जोड़ने की दिक्कत को दूर करने के लिए अपनाया गया है जिससे कि पाटन मार्जिन के स्तर को पूर्व निर्धारित स्तर के अनुरूप ही रखा जा सके।
- च. चूंकि आवेदक द्वारा 4एडीपीए की प्रस्तुत की गई कीमतों में 15 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क समाहित किया गया है, इसलिए यह अपेक्षित है कि पहले उस शुल्क को घटाया जाए और फिर निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नया दावा किया जाए जिससे कि वह इस दावे को स्वीकार कर सकें।
- छ. आवेदक ने केपीसी की उपभोग कीमत का प्रतिस्थापन किए जाने का दावा किया है। परंतु यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तुत की गई कीमत का ऐसे सभी खर्चों के लिए समायोजन करना चाहिए। आवेदक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 01.10.2008 को अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले कभी नहीं उठाया अथवा उसने इस मुद्दे को न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अपील में उठाया कि ऐसे समायोजन किए जाने चाहिए। इसलिए इस मुद्दे को इस स्थिति में उठाने की कोई आजादी नहीं है।
- ज. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे केपीसी द्वारा दायर प्रश्नावली के प्रत्युत्तर की संपूर्णता और यथार्थता के मुद्दे पर दिनांक 01.10.2008 को जारी अंतिम जांच परिणाम की समीक्षा करें। माननीय सेस्टेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केपीसी द्वितीय परिवहन और समुद्रपार परिवहन का विश्लेषण प्रदान करने में असफल रहा है। किसी भी प्राधिकारी को अपने स्वतः आदेश की पुनरीक्षा करने और उसे किसी ऐसे पक्षकार के विरुद्ध धारित करने की अनुमति नहीं है जिसे उस पक्षकार की अपील पर वह मामला रिमांड किया गया है, जिससे कि विगतवर्ती आदेश को किसी भी रूप में न्यायोचित ठहराया जा सके। द्वितीयतः प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई ऐसा प्रश्नावली प्ररूप नहीं है जिसमें परिवहन लागत का ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित हो।
- झ. 4एडीपीए का जर्मनी से प्रदायक और भारत में केता संबद्ध पक्षकार नहीं हैं जैसेकि केपीसी और सिनोर्गेकिम हैं और इसलिए आवश्यक समायोजनों की अनुमति प्रदान करने के लिए ऋण शर्तों की जांच किया जाना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी "उपलब्ध तथ्यों" की मनमाने ढंग से अनदेखी नहीं कर सकते हैं।
- ञ. प्राधिकारी ने इस आशय का कोई कारण नहीं दर्शाया है कि व्याज व्ययों से संबंधित उनका पिछला निर्णय किस तरह गलत था। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों को किसी भी हाल में किसी ऐसे मुद्दे का पुनर्निर्धारण करके, जो रिमांड आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी के समक्ष मुक्त नहीं है, प्रतिवादियों के बदतर स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता है।
- ट. दिनांक 01.10.2008 के अंतिम जांच परिणाम में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि सिनोर्गेकिम द्वारा भारत को 4एडीपीए की कीमत केपीसी को 4एडीपीए की कीमत से अधिक है। इस अंतर का कारण मात्रा डिस्काउंट था। रिकार्ड में उपलब्ध इस तथ्य की

अनदेखी नहीं की जा सकती है। 4एडीपीए की नवीन प्रतिस्थापित कीमत का समायोजन करने के रूप में उसी अंतर की अनुमति दी जानी चाहिए।

ठ. निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वे कोरिया में पत्तन के लिए अभिव्यक्त खर्चों का निर्धारण करने के आधार का प्रकटन करें :

- (i) केवल संव्यवहारवार आयात आंकड़े ही उपलब्ध कराए गए थे। वह आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि उक्त मूल्य कर निर्धार्य मूल्य है अथवा इस मूल्य का निर्धारण अन्य खर्चों का समायोजन किए जाने के पश्चात् किया गया है। इसलिए, यह आकलन किया जा सकता है कि इस मूल्य में सभी समायोजन शामिल हैं।
- (ii) आयातक (कालम च) के नीचे के कालम में दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि "कंपनी ज्ञात नहीं है"। तथापि, एक्सेल फाइल के टाप पर "लैनेक्सेस" नाम दर्शाया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि यह आंकड़े लैनेक्सेस द्वारा प्रदान किए गए हैं अथवा वह आंकड़े आईबीआईएस ने प्रदान कराए हैं। इन आंकड़ों में चीन जन.गण. से आयातों को भी शामिल किया गया है। माननीय न्यायाधिकरण ने पहले ही यह धारित किया है कि यदि कच्चे माल का आयात चीन से किया जाता है कि तो उसमें सामान्य मूल्य की संरचना को भी शामिल किया जाना चाहिए और अंतिम जांच परिणाम में उसी सीमा तक संशोधन किया जाए।
- (iii) उन आंकड़ों में दर्शाया गया मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस समय सीमाशुल्क द्वारा वस्तु की निकासी की जाती थी। जरूरी नहीं है कि यह मूल्य सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आकलित अंतिम आयात मूल्य हो। वस्तुओं की निकासी वर्तमान मामले में संबद्ध पक्षकार के सौदों के संबंध में कई मुद्दों के कारण अनन्तिम आकलन आधार पर भी की जा सकती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए।
- (iv) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वर्तमान मामले में संबद्ध पक्षकार के सौदों के संबंध में वस्तु की निकासी कई मुद्दों के कारण अनन्तिम आकलन आधार पर की जा सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।
- (v) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत 4एडीपीए की आयात की यथार्थता का किसी साधन से स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है।

ड. प्राधिकारी को परिकलन एक्सेल शीट में प्रदान कराए जाने चाहिए जिनमें परिकलन क्रियापद्धति और अभिव्यक्त पाटन मार्जिन पर पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए स्पष्टीकरण का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए। प्रतिवादीगण हार्ड प्रति के आधार पर अपनी अभ्युक्तियां प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. यद्यपि प्रतिवादित सीमा शुल्क अधिसूचना और अंतिम जांच-परिणाम में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विभिन्न रबड़ रसायन अर्थात् एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा कोरिया आरपी के मूल का अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) था, तथापि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादित अपील में इस दायरे को केवल कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों तक सीमित कर दिया। इसलिए, निर्णय पश्चात् मौजूदा जांच का दायरा कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों तक ही सीमित है। पीएक्स-13 (6पीपीडी) एक रबड़ रसायन होता है जिसका रासायनिक विवरण एन-(1,3-डाइमिथायल ब्यूटायल) – एन फिनायल-पी-1 होता है और उसके अन्य व्यापार/ब्रैंड नाम 6सी, पिल्फ्लेक्स 13, सायरनटाक्स 4020 एंटीआक्सीडेंट 4020, कुम्होनेक्स 13 बुल्कैनाक्स 4020 आदि हैं।

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी को इस मामले की याद दिलाते हुए न्यायाधिकरण ने निर्णय पश्चात् सुनवाई के दायरे को सीमित करते हुए विशिष्ट आदेश पारित किए और इस रिमांड जांच में दायरे का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया है :

- (क) 6पीपीडी जहां तक उसका संबंध कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स से है, की निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रकटन करना।
- (ख) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई "क्रियापद्धति" का प्रकटन करना।

17. इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते का प्रस्ताव करते हैं कि इस निर्णय पश्चात् मौजूदा सुनवाई और पुनर्निर्धारण का दायरा पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित मुद्दों से परे अधिक नहीं होना चाहिए।

18. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सेस्टेट ने वर्तमान रिमांड मामले में पारित सेस्टेट के दिनांक 26.12.2014 के आदेश का दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 744/2015 के आदेश द्वारा खंडन किया है, यह नोट किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय केवल सैनडिस्क मामले तक सीमित है और यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका सेस्टेट के आदेश पर कोई प्रभाव है क्योंकि सेस्टेट के इस आदेश का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं किया गया है।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सेस्टेट के दिनांक 26.12.2014 के इस आदेश के खिलाफ कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कोरिया आरपी (केपीसी), ऋषिरूप पालिमर्स और एनओसीआईएल, घरेलू उद्योग द्वारा विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई है।

20. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि केपीसी तथा ऋषिरूप पालीमर्स ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12086-12087/2015 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क भी दिया है कि प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारण करने के लिए इस मामले के संबंध में सेस्टेट द्वारा दिया गया उपर्युक्त आदेश अवैध है और उसके जांच-परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। केपीसी और ऋषिरूप पालीमर्स ने यह तर्क दिया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और निर्णय के पश्चात् की सुनवाई एक उपयुक्त समाधान नहीं है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करते हुए सीमा शुल्क अधिसूचना को प्रभावित हुए काफी समय बीत गया है। उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि सेस्टेट, जिसने हितबद्ध पक्षकारों के अधिकतर तर्कों को अस्वीकार कर दिया, ने हितबद्ध पक्षकारों के ज्यादातर प्रस्तुतिकरणों पर तो विचार ही नहीं किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उत्पादन लागत का मूल्यांकन उचित लागत के रूप में नहीं किया गया और यह कि निर्यातित वस्तु की कीमतें पाटन के कारण कम नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया कि प्राधिकारी द्वारा किया गया सामान्य मूल्य का निर्धारण अयथार्थ है।

21. दूसरी और घरेलू उद्योग ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8088/2015 में यह तर्क दिया है कि 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का कोरियाई निर्यातकों द्वारा खंडन नहीं किया गया है और यह कि इसका निर्धारण करने में होने वाली किसी भी विसंगति पर टिप्पणी करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था और इसलिए उनके इस तर्क में कोई देय नहीं है। सेस्टेट द्वारा इस तथ्य की अनदेखी कर दी गई और यह मामला प्राधिकारी को पुनर्प्रेषित कर दिया गया। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया कि सेस्टेट इस तथ्य से सहमत नहीं है कि केपीसी ने यह अभिवचन किया है कि उसे प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आंकड़ों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और केवल यह बहाना बनाया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सकल उल्लंघन किया गया है।

22. इन सभी तीनों विशेष अनुमति याचिकाओं पर 8 मई, 2015 को सुनवाई हुई जिनमें, पक्षकारों को सुनने के पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन पक्षकारों को अनुमति प्रदान करने से मना कर दिया और अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। माननीय न्यायालय ने निम्नवत प्रेक्षण किया है :

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने, अनुदेश दिए जाने पर, याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की यथार्थता अथवा अन्यथा के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी उपयुक्त मंच के समक्ष, इन विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाए गए तर्कों सहित, उनको उपलब्ध सभी तर्क प्रस्तुत करके, इन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने की न्यायालय से अनुमति मांगी है। मांगी गई अनुमति प्रदान की जाती है।"

23. अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण कर दिया और वे अब उपर्युक्त की इच्छा से वापस ले ली गई हैं।

24. अतः, यह नोट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न तो यह निर्णय दिया कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले पर पुनः निर्धारण करने के लिए इस मामले को प्राधिकारी को पुनः दिया जाना अनुपयुक्त है और न ही उच्चतम न्यायालय ने कभी यह निर्णय दिया कि न्यायाधिकरण को यह मामला पुनर्निर्धारण हेतु प्राधिकारी के पास पुनर्प्रेषित नहीं करना चाहिए था।

25. जहां तक रिमांड की कार्यवाही में विलंब के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने दिनांक 03 अगस्त, 2015 को एक प्रकटन विवरण पहले ही जारी कर दिया परंतु अचानक प्रशासनिक परिवर्तन होने और निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में एक नए अधिकारी की नियुक्ति होने के कारण द्वितीय मौखिक सुनवाई का आयोजन किया गया। वर्ष 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.01.2011 के निर्णय के अनुरूप नए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 23.08.2015 को द्वितीय मौखिक सुनवाई का आयोजन किया।

26. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि केपीसी ने वस्तु का पाटन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती समीक्षाओं में परिणामी शुल्क का कोई विस्तार करना अथवा उसकी निरंतरता बनाए रखना भी वैध नहीं है, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक था।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह मामला प्राधिकारी को वापस रिमांड करते समय न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया है कि प्राधिकारी पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करेंगे। इसलिए, जहां तक कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स का संबंध है वर्तमान जांच का दायरा उसके पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करना है।

28. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को किसी रिमांड की कार्यवाही में मालभाड़ा, प्रहस्तन प्रभार और सीमा शुल्क में समायोजन करने के मुद्दे की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी को कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के संबंध में निर्यात कीमत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करना अपेक्षित है। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने में ऐसे निर्धारण के सभी पहलू शामिल होंगे जिनमें मालभाड़े, प्रहस्तन प्रभार और सीमाशुल्क में समायोजन करने का मुद्दा भी शामिल है।

29. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में शब्द "सीआईएफ" का पहली बार प्रयोग किया है क्योंकि यह शब्द अंतिम जांच परिणाम में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका संक्षेप में कारण यह है कि प्रतिवादी निर्यातक ने एक अपील दायर की थी और न्यायाधिकरण ने 4एडीपीए के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कीमत का प्रकटन करने की कार्यवाही को रिमांड कर दिया है। इसलिए, प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि अपनाई गई कीमत सीआईएफ आयात कीमत है। जहां तक इस संबंध में घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि प्राधिकारी को सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए भारत में उपभोग कीमत को अपनाना चाहिए और फिर उसके पश्चात् समुचित समायोजन करना चाहिए इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि जब सीआईएफ आयात कीमत स्वयं की उपलब्ध है तो पहले भारत में आयात होने के पश्चात् के विभिन्न व्ययों को जोड़ने और फिर उसको घटाने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि प्राधिकारी को कोरिया में उपभोग कीमत का निर्धारण करना अपेक्षित था, इसलिए प्राधिकारी ने सीआईएफ आयात कीमत पर विचार किया और फिर कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स की उपयोग कीमत का निर्धारण करने के लिए समुचित समायोजन किए हैं।

30. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को अंतरदेशीय मालभाड़े के संबंध में केपीसी द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर की यथार्थता और संपूर्णता की समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णय के पश्चात् सुनवाई का दायरा कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के संबंध में निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करना है। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने में ऐसे निर्धारण के सभी पहलू शामिल होंगे जिनमें मालभाड़ा, प्रहस्तन प्रभारों और सीमाशुल्क का समायोजन करने का मुद्दा भी शामिल है।

31. जहां तक जर्मनी से 4एडीपीए की कीमतों का संबद्ध पक्षकार के सौदे होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लैनेक्स इंडिया द्वारा लैनेक्स जर्मनी से 4एडीपीए के लिए किए आयात को भिन्न बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों में स्थित संबद्ध कंपनियों के बीच हैं और किसी वास्तविक साक्ष्य के अभाव में, यह विचार किया जाना चाहिए कि जब तक प्राधिकारी के संज्ञान में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं लाया जाता है तब तक इन्हें निकट आधार पर ही माना जाएगा।

32. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इस मामले में संबद्ध पक्षकार के सौदों के संबंध में विभिन्न मुद्दों के कारण वस्तु की निकासी अनन्तिम आकलन आधार पर की जा सकती थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई तर्क नहीं दिया है।

33. जहां तक आयात कीमत परिकलनों को एक्सेल शीट में प्रदान कराए जाने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विधि के अंतर्गत न तो ऐसी कोई विहित अपेक्षा है और न ही मौजूदा मामले में यह सिद्ध होता है कि उक्त सूचना आवश्यक है अथवा यह किसी भी रूप में निर्यातक को अपनी टिप्पणियां देने में अक्षम ठहराती है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई आयात लिस्टिंग स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि बहुत कम संख्या में सौदे किए गए हैं और उनमें से भी कुछ कीमत बैंडों में आते हैं।

34. प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड) द्वारा रिपोर्ट की गई 4एपीडीए की खपत कीमत की उपयुक्तता अथवा अन्यथा की स्वीकृति मौजूदा पुनः निर्धारण के दायरे से परे है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सेस्टैट ने केपीसी द्वारा रिपोर्ट की गई 4एपीडीए के खपत कीमत को अस्वीकार करने के प्राधिकारी के निर्णय की परिपुष्टि की।

35. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि केपीसी की उत्पादन लागत की संरचना करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति, सत्यापन रिपोर्ट, इन सत्यापन रिपोर्टों पर केपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां, जो अपनाई गई क्रियापद्धति और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आधार बनी, के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया है, इसलिए घरेलू उद्योग को जिस सूचना का प्रकटन किया गया है वह अपर्याप्त है। प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि इस मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ इस मामले को पुनर्प्रेषित करते समय न्यायाधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा मांगी गई सूचना का प्रकटन करने के लिए ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की रिकार्डिंग इस न्यायाधिकरण के आदेश से भिन्न है। इस न्यायाधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा सुनवाई के समय उठाए गए तर्कों

को ही रिकार्ड किया है। न्यायाधिकरण ने इन दस्तावेजों का प्रकटन करने के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया है। तथापि, चूंकि न्यायाधिकरण ने प्राधिकारी को पाटन मार्जिन का पुनः निर्धारण करने के लिए निदेश दिया है, प्राधिकारी ने तथ्यों का सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त रूप से प्रकटन किया है, जहां तक इनका संबंध केपीसी के बारे में पाटन मार्जिन का निर्धारण करने से संबंधित है। प्राधिकारी ने ब्याज लागत, स्टीम लागत, एसजीए व्यय, ग्राही अंतर्निविष्टियों का मूल्यांकन, व्यय की संगणना करने के संबंध में उपयुक्त ही प्रकटन किया है जिसमें 4एडीपीए की खपत कीमत का निर्धारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत को जोड़ा जाना चाहिए।

36. जहां तक शुल्क प्रति अदायगी, भाड़ा अंतर का समायोजन करने और अन्य खर्चों को जोड़ने में ऋणात्मक घटौती करने का संबंध है, प्राधिकारी ने इस संबंध में निम्नवत नोट किया है :

- (क) **भाड़ा अंतर :** प्राधिकारी द्वारा 4एडीपीए की अंगीकार की गई उपभोग लागत जर्मनी से भारत को 4एडीपीए की सीआईएफ निर्यात कीमत पर आधारित थी। केपीसी ने यह तर्क दिया है कि जर्मनी से भारत को निर्यात भाड़ा और चीन से कोरिया आरपी को निर्यात का भाड़ा अंतर को समायोजित करना चाहिए। तथापि, निर्यातक ने इस संबंध में अपने दावे का परिमाणन नहीं किया है और इसलिए, चूंकि प्राधिकारी ने केपीसी के तर्कों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए प्राधिकारी ने इस अंतर की अनुमति इस संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर दी है। प्राधिकारी ने, उसी उत्पाद के लिए निर्णायक समीक्षा जांच आयोजित करते समय केपीसी के उन तर्कों को नोट किया है कि इस उत्पाद के आयातों से संबंधित व्ययों में इसमें अंतर्ग्रस्त दूरी के आधार पर अंतर होता है। प्राधिकारी ने अपनी निर्णायक समीक्षा जांच में (दिनांक 29 अप्रैल, 2014 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/1/2013-डीजीएडी) चीन से कोरिया आरपी को भाड़ा और जर्मनी से भारत को भाड़े के बीच भाड़े में अंतर के लिए कीमत का उपयुक्त समायोजन किया था। इसलिए, इस संबंध में केपीसी द्वारा कोई भी दावा न किए जाने को ध्यान में रखते हुए भाड़े में अंतर के संबंध में उस पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में विचार करते हुए उपभोग लागत को 50 यूएस डालर पीएमटी की राशि तक कम कर दिया था। चूंकि केपीसी ने कोई परिमाणित दावा नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में भी उसी अंतर को अपनाया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केपीसी की उपभोग कीमत का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित व्ययों को जोड़ना/घटाना महत्वपूर्ण है।
- (ख) **कोरिया आरपी में पत्तन व्यय :** चूंकि 4एडीपीए की विचारी गई कीमत में पत्तन व्यय शामिल नहीं होती है और चूंकि इस उत्पाद के आयातों में पत्तन प्रभार शामिल होना चाहिए, इसलिए प्राधिकारी ने कोरिया में पत्तन व्यय के रूप में सीआईएफ आयात कीमत का *** प्रतिशत जोड़ा है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केपीसी ने कोई संगत सूचना प्रदान नहीं की है और इसलिए इस राशि को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर अपनाया गया है।
- (ग) **कोरिया आरपी में आयातों पर देय सीमाशुल्क :** 4एडीपीए के आयातों पर कोरिया में *** प्रतिशत सीमाशुल्क का भुगतान करना अंतर्ग्रस्त होता है। इसलिए, उसे सीआईएफ आयात कीमत में जोड़ा गया है।
- (घ) **पत्तन से कारखाने तक अंतःस्थलीय भाड़ा :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने उस व्यय की रिपोर्ट नहीं की है जिसे निर्यातक ने वस्तु का अधिप्रापण करने, उसका पत्तन से अपनी फैक्ट्री तक पोतलदान करने पर उपगत व्यय की रिपोर्ट नहीं की है। निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई खपत लागत में इन व्ययों का पृथक-पृथक व्यौरा नहीं दिया गया है। निर्यातक द्वारा अपनी फैक्ट्री से भारतीय समुद्री पत्तन तक निर्यात करने पर व्यय किए गए भाड़े के संबंध में सूचना पर निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में उपलब्ध कराए गए अपर्याप्त विवरण के कारण विचार नहीं किया जा सका। प्राधिकारी ने इस व्यय को *** प्रतिशत की दर से निर्धारित करने का निर्णय उपयुक्त माना है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में निर्यातक से वास्तव में यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंतःस्थलीय परिवहन और सामुद्रिक परिवहन का अलग-अलग विवरण प्रदान कराए। तथापि, निर्यातक ने इस संबंध में विहित स्वरूप और ढंग से सूचना प्रदान नहीं की है।
- (ङ) जहां तक शुल्क प्रतिअदायगी समायोजन की अस्वीकृति का संबंध है, इस समायोजन की स्वीकृत अथवा अस्वीकृति करने के लिए किसी सीधे जैकेट अधिगम की आवश्यकता नहीं है। उक्त समायोजन की अनुमति उत्पादक/निर्यातक के दावों का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात् मामला-दर-मामला आधार पर दी जाती है। यदि कोई उत्पादक/निर्यातक सत्यापन दल को उक्त समायोजन के समर्थन में संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है तो इस समायोजन की अनुमति दे दी जाती है। आवेदक द्वारा उद्धृत किए गए मामलों में उत्पादक/निर्यातक इस संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने में प्रयोग किए गए कच्चे माल पर संदत्त आयात शुल्क विवरण दर्शाने वाले और भारत तथा अन्य देशों को किए गए निर्यातों के कारण प्राप्त एवं दावाकृत शुल्क प्रति अदायगी को दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं कर सके हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा उद्धृत किए गए मामलों में से एक मामले में शुल्क प्रति अदायगी की अनुमति किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक को दी गई थी क्योंकि उसका दावा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित था। चूंकि यह एक रिमांड मामला है और प्राधिकारी ने विधिवत सत्यापन के पश्चात् मूल जांच के समय पर ही समायोजन का पहले ही सत्यापन कर दिया और उसकी अनुमति दे दी है, इस स्तर पर शुल्क प्रति-अदायगी के समायोजन की अनुमति न देने के घरेलू उद्योग के तर्क में कोई दम नहीं है।

37. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को कम करके उल्लिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह तर्क भी दिया है कि इस प्रकार की न्यूनोक्तियां उन व्ययों के कारण हो सकती हैं जिन्हें इस वस्तु का उत्पादन करने में स्टीम, ब्याज लागत, एसजीए खर्चों, ग्राही अंतर्निविष्टियों आदि के रूप में उपगत किया जाना अपेक्षित होता है।

38. जहां तक 15 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क की कटौती करने के तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी 4एडीपीए की सीआईएफ आयात कीमतों पर विचार किया है और इसलिए अपनाई गई कीमत में सीमाशुल्क को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि सीमाशुल्क को शामिल नहीं किया गया है इसलिए उसका अपवर्जन करना अपेक्षित नहीं है।

39. जहां तक केपीसी के इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत विभिन्न व्ययों का समायोजन पहले ही कर दिया है, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने भारत में सीआईएफ आयात कीमतों पर विचार किया है और उसका प्रतिस्थापन केपीसी द्वारा रिपोर्ट की गई उपभोग कीमत से किया है। इसलिए, भारत में सीआईएफ आयात कीमत को विभिन्न व्ययों के लिए समायोजित किया जाना और फिर उसके पश्चात् उपभोग कीमत का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अब यह कार्य कर लिया गया है।

40. जहां तक ग्राही अंतर्निविष्टियों का संबंध है, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए दावे को कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के आधार पर अपनाया है।

41. जहां तक स्टीम व्ययों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक स्टीम का उत्पादन विभिन्न उत्पादों में उपभोग करने के लिए करता है। निर्यातक स्टीम का उत्पादन केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए ही नहीं करता है। वाष्प के आधार पर निर्यातक द्वारा प्रभारित किए गए व्यय कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के आधार पर हैं। उसने वाष्प पर व्यय का विशिष्ट आबंटन किया और वर्तमान प्रयोजन के लिए उसे ही अपनाया गया है।

42. जहां तक एसजीए व्ययों का संबंध है, प्राधिकारी ने एसजीए व्ययों का संविभाजन करने के लिए कारोबार अनुपात को अपनाया है।

43. जहां तक ब्याज व्यय का संबंध है, प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा किए गए ब्याज व्यय पर विचार, ब्याज आय को शामिल न करते हुए किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी द्वारा अर्जित की गई ब्याज आय, अन्य व्यवसाय प्रचालनों (अर्थात् वित्तीय प्रचालनों) के लिए होती है। इसलिए, इस ब्याज आय को ब्याज व्यय से घटाया नहीं जा सकता है। ब्याज आय का अपवर्जन करने के पश्चात् ब्याज लागत का निर्धारण किया गया है। विभिन्न उत्पादों पर निवल ब्याज व्यय का संविभाजन प्रतिनिधिक कारोबार के आधार पर किया है।

44. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को आयात आंकड़ों का अधिप्रापण अपने निजी स्रोतों से करना चाहिए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि न तो मूल जांच के समय और न ही न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के समय, न ही निर्णय पश्चात् वर्तमान सुनवाई के समय, निर्यातक, आयातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी सूचना प्रदान नहीं कराई है जिसे वर्तमान प्रयोजन के लिए अपनाया जा सकता हो। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि यह हितबद्ध पक्षकारों के लिए खुला है कि वे तर्क प्रदान करें, परंतु उनका यह उत्तरदायित्व भी है कि वह ऐसी सूचना प्रदान करें जिसे वे संगत और उपयुक्त मानते हों।

45. जहां तक आईबीआईएस द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की प्रामाणिकता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने विगत में की गई कई जांचों में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कई गौण स्रोतों, जिनमें आईबीआईएस भी शामिल है, द्वारा प्रदान कराई गई सूचना को अपनाया है। आईबीआईएस एक स्वतंत्र विशेषीकृत गैर-सरकारी एजेंसी है और आईबीआईएस द्वारा प्रदान कराई गई सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित होती है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आईबीआईएस सूचना प्रदान कराने का उद्देश्य अंतर्निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का निर्धारण करना था। हालांकि उस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग का दावा भारत को 4एडीपीए के आयातों के व्यापक लेखाओं पर आधारित था; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि, हर हाल में, इस सूचना का प्रयोग करने का उद्देश्य 4एडीपीए की युक्तियुक्त तथा प्रतिनिधिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत का निर्धारण करना है। यह तर्क न तो किसी निर्यातक, आयातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार का है, न ही यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रदान कराने वाले किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार का है, कि किसी सौदे का संभावित अपवर्जन अथवा समावेशन से, वर्तमान निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई *** यूएस डालर की परिणामी कीमत को विकृत किया है। प्राधिकारी भारत को 4एडीपीए के आयातों के सौदेवार विवरणों से यह भी नोट करते हैं कि उक्त सूचना अत्यधिक उच्च अथवा न्यून कीमत को नहीं दर्शाती है। इसके विपरीत उक्त सूचना यह दर्शाती है कि एक ही कीमत पर भारी संख्या में सौदे किए गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने 4एडीपीए की कीमतों को उचित स्थापन करने के पश्चात् ही अपनाया है।

46. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को यह निरूपित करना चाहिए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कीमत का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पत्तनों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों डीजीसीआईएंडएस, संपूर्ण विश्व में भारतीय राजदूतावासों को लिखा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इन जैसी विभिन्न एजेंसियों से सूचना मंगाए। नियम 6 में उस ढंग से संबंध में विशिष्ट दायित्व का निर्धारण किया गया है जिस ढंग में इस जांच का आयोजन किया जाना चाहिए, वह स्रोत जहां से सूचना अवाप्त की जानी चाहिए और वह ढंग जिसमें सूचना को प्रसंसाधित किया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए। यद्यपि प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकारी है कि वह संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातों तथा प्रयोक्ताओं को अवसर प्रदान करें, तथापि ऐसा कोई विधिक अधिदेश नहीं है कि प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सुनिश्चयन करने के लिए देश के विभिन्न पत्तनों अथवा संपूर्ण विश्व में स्थित भारत के विभिन्न राजदूतावासों अथवा उस उद्देश्य के लिए डीजीसीआईएंडएस को पत्र लिखें। यह वह मामला नहीं है जहां कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ साक्ष्य प्रदान कराए हों और प्राधिकारी ने उन साक्ष्यों की अनदेखी कर दी हो। संगत सूचना प्रदान करने का दायित्व घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और इन पक्षकारों की एसोसिएशनों का है।

47. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यह जांच आयोजित करने का दायित्व प्राधिकारी का है और घरेलू उद्योग का यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह आंशिक रूप से जांच का आयोजन करे, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी ने मूल जांच का आयोजन किया था और पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्धारण भी किया था। वर्तमान पुनर्निर्धारण भी प्राधिकारी द्वारा ही किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए अथवा इस मामले में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं छोड़ा गया है। हितबद्ध पक्षकारों के पास केवल एक ही अधिकार है और उस अधिकार विशेष रूप से प्रावधान पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में किया गया है।

48. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने विगत में गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचना को अस्वीकार कर दिया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में किसी सूचना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर आधारित होता है। यह कहना कि केवल इस कारण कि गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदान कराई गई सूचना को अपूर्ण पाया गया और कुछ अन्य जांचों में उसकी अवहेलना कर दी गई, इसका आशय यह नहीं है कि वर्तमान मामले में प्रदान कराई गई सूचना अपूर्ण है और उसकी अवहेलना कर दी जानी चाहिए अथवा उस सूचना के स्रोत को ही सदैव के लिए अनुपयुक्त मान लिया जाए। वास्तव में प्राधिकारी नैतिक रूप से यह उपपादित करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा कभी-कभार गौण स्रोतों से रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा की तुलना में कम होती है, जबकि डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा कभी-कभार कुछ अन्य मामलों में गौण स्रोतों से रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा की तुलना में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में मुद्दा आयातों की कीमत और मात्रा दोनों में अंतर्ग्रस्त होता है। आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करने के प्रयोजन के लिए संगत होती है, और आयातों की मात्रा और मूल्य आयात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए संगत होता है। इसलिए प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए आयात की मात्रा और मूल्य दोनों पर विचार करते हैं। इसलिए उस प्रयोजन के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अपनाए गए आयात आंकड़े उस उत्पाद के आयातों का सर्वाधिक विस्तृत विवरण का प्रतिनिधित्व करते हों। तथापि, वर्तमान उद्देश्य के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपनाए गए आयात आंकड़े 4एडीपीए के सर्वाधिक विस्तृत विवरण का प्रतिनिधित्व करते हों। महत्वपूर्ण एवं संगत मापदंड यह है कि 4एडीपीए की परिणामी आयात कीमत युक्तियुक्त हो और वह उस उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए जिन आयात सौदों पर विचार किया गया है वे केवल 4एडीपीए के आयातों से संबंधित हैं और उनमें कोई अति उच्च अथवा कम कीमत शामिल नहीं है।

49. जहां तक भुगतान की शर्तों का संबंध है प्राधिकारी भुगतान की उन शर्तों पर विचार नहीं करते हैं जो निर्यातक और कच्चे माल के प्रदायकों के बीच तय हुई हों और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इसे सिद्ध किया गया है कि कच्चे माल का प्रापण करते समय भुगतान की शर्तें संगत कारक थीं। जब साइनोर्गेकिम से केपीसी द्वारा खरीदे गए 4एडीपीए के संबंध में भुगतान की शर्तों और सुपुर्दगी की शर्तों पर संगत पैरामीटरों के रूप में तर्क नहीं दिया गया है तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जर्मनी के प्रदायक तथा भारत के क्रेता के बीच भुगतान की शर्तें और सुपुर्दगी की शर्तें वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत होंगी।

50. जहां तक भाड़ा लागत में अंतर का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कीमत भारत में सीआईएफ आयात कीमत थी और भाड़े में अंतर के लिए उसका ही समुचित ढंग से समायोजन किया गया है।

51. आयातक और निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए 4एडीपीए के आयात सौदे लैनेक्सेस जर्मनी और लैनेक्सेस भारत के बीच किए गए सौदे हो सकते हैं, और इसलिए इन दोनों के बीच संबंध होने के कारण सौदा मूल्य विकृत हो सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने निर्यातक और आयातक द्वारा रिपोर्ट किए गए बीजक मूल्य को नहीं अपनाया है। प्राधिकारी ने सीमाशुल्क का आकलन करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सौदा मूल्य को अपनाया है। किसी भी हाल में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी पक्षकार द्वारा यह निरूपित नहीं किया गया है कि इस संबंध में कारण आयात कीमत वास्तव में प्रभावित है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी केवल इस संभावना अथवा संयोग के आधार पर ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

कि हो सकता है कि संभावित संबंधों के कारण आयात कीमत पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की परिकल्पनात्मक स्थिति उनके दावों के संबंध में आधार नहीं बन सकती है जब तक कि उसको दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है और एतद्वारा हितबद्ध पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे अपना तर्क प्रस्तुत करते समय अपने तर्क को सिद्ध करें। वर्तमान मामले में, यह सिद्ध करने के लिए कि उक्त संबंध के कारण आयात कीमत पर वास्तव में कोई प्रभाव पड़ा है, कोई तर्क नहीं दिया गया है। द

52. जहां तक चीन से आयात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन से आयात कीमत को अपनाया जाना वर्तमान पुनर्निर्धारण के लिए मुक्त नहीं है। किसी भी हाल में, चीन से आयात कीमत को ठीक उसी कारण से नहीं अपनाया जा सकता है, जिसके लिए केपीसी की उपभोग कीमत को नहीं अपनाया गया है। यदि निर्यातक की उपभोग कीमत को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह कृत्रिम रूप से कम थी, तो भारत में आयात कीमत को ही उसी कारण से नहीं अपनाया जा सकता है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि साइनोर्गेकिम के पास 4एडीपीए के लिए उसकी अपनी जरूरत की तुलना में कहीं अधिक क्षमता है और वह कच्चे माल की कम कीमत पर बिक्री करके इस विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहा था।

53. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि केपीसी द्वारा साइनोर्गेकिम से लाई गई बाड़ी मात्रा पर विचार करते हुए, खपत कीमत पर कुछ मात्रा डिस्काउंट होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केपीसी ने यह निरूपित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि जब भारी मात्रा में खरीद की जाती है तो बिक्रेताओं द्वारा निरपवाद रूप से मात्रा डिस्काउंट दिया जाता है। यह उपयुक्त नहीं है कि उस अनुपात का सामान्यीकरण किया जाए कि यदि किसी वस्तु की मात्रा अधिक है तो उसकी बिक्री कीमत कम होगी। वास्तव में, यह पूर्णतया संभव है कि कम मात्रा होने पर भी बिक्री कीमत कम हो सकती है। किसी भी हाल में, यह एक तथ्य का सवाल है जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए।

54. जहां तक अपनाए गए भिन्न विनिमय दरों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अपनाए गए विनिमय दर में कोई अंतर नहीं है। प्रासंगिक भारित औसत निर्यात दरें एसोसिएटेड मात्रा में अंतर होने के कारण अंतर है। अधोलिखित तालिका यह दर्शाती है कि अपनाई गई विनिमय दरें समान थी :

विवरण	मात्रा किलोग्राम में	औसत विनिमय दर
चीन जन.गण.		
अप्रैल-06	80,000	44.85
जून-06	64,000	46.20
जुलाई-06	83,360	46.55
अगस्त-06	32,000	47.20
सितम्बर-06	64,000	46.80
अक्तूबर-06	64,000	46.15
नवम्बर-06	128,000	45.55
जनवरी-07	112,000	44.70
फरवरी-07	112,000	44.45
मार्च-07	112,000	44.45
कुल चीन जन.गण.	851,360	45.69
जर्मनी		
अप्रैल-06	241,100	44.85
मई-06	108,380	45.35
जून-06	154,820	46.20
जुलाई-06	109,100	46.55
अगस्त-06	44,160	47.20
सितम्बर-06	44,260	46.80
अक्तूबर-06	88,500	46.15

नवम्बर-06	89,820	45.55
दिसम्बर-06	133,220	44.95
जनवरी-07	109,540	44.70
फरवरी-07	66,320	44.45
मार्च-07	43,840	44.45
कुल जर्मनी	1,233,060	45.60

55. जहां तक उस तर्कसंगत लाभ का संबंध है, जिसे वर्तमान प्रयोजन के लिए अपनाया जाना चाहिए, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई किसी अन्य सूचना के अभाव में अपनी सुस्थापित परम्परा के अनुसार ब्याज का अपवर्जन करके बिक्री लागत के ***प्रतिशत को लाभ के रूप में माना है।

56. जहां तक केपीसी के इस तर्क का संबंध है कि सेस्टैट ने 4एडीपीए को अस्वीकार करने के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय की परिपुष्टि इस प्रकल्पना पर की है कि एक भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय कीमत मौजूद है, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि केपीसी का यह तर्क निराधार है। वास्तव में, प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए *** यूएस डालर के आंकड़ों तथा उसके आधार को न्यायाधिकरण द्वारा अभिस्वीकार किया गया था। न्यायाधिकरण का प्रेक्षण यह था कि निर्धारण करते समय उक्त आंकड़ों का प्रकटन निर्यातक, आयातक अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया था। वास्तव में, न्यायाधिकरण ने प्राधिकारी को निदेश दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कीमत का प्रकटन करें और यह प्रतिपादित नहीं किया है कि प्राधिकारी अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय कीमत की उपयुक्तता पर पुनर्विचार करें। प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत का प्रकटन करना, अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय कीमत की उपयुक्तता पर विचार करने से भिन्न है।

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संबंध में सूचना जर्मनी से भारत को इस उत्पाद के लिए गए आयातों के अपने कई प्रस्तुतिकरणों के आधार पर उपलब्ध कराई है। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से अपनी सुनवाई पुस्तिका (पेपर बुक), सुनवाई के पश्चात् किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों और दिनांक 6 फरवरी, 2008 के पत्र में 4एडीपीए के आयातों के सौदों के सौदेवार आंकड़े प्रदान कराए हैं जो *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम की आयात कीमत का आधार बनता है। इन प्रस्तुतिकरणों ने निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि घरेलू उद्योग का दावा उनके द्वारा आईबीआई से अधिप्राप्त की गई सूचना के अनुरूप 4एडीपीए के आयातों पर आधारित हैं। घरेलू उद्योग ने इन प्रस्तुतिकरणों के अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराए हैं, जिन्हें सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सहित, हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए प्रस्तुतिकरणों की प्रत्युक्तियां दायर कर दी हैं और इसलिए इन आईबीआईएस आंकड़ों अथवा भारत में 4एडीपीए के आयातों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा यथादावाकृत *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम की आयात कीमत की परिशुद्धता अथवा अन्यथा के संबंध में टिप्पणियां करने का पर्याप्त अवसर था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकार यह तर्क दे सकते थे कि उन्हें प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए *** यूएस डालर के आंकड़ों अथवा उनके स्रोत के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, तथापि हितबद्ध पक्षकार यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि उन्हें इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे पर टिप्पणियां करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह भी सुस्पष्ट है कि घरेलू उद्योग इस जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान कोरियाई निर्यातक की उत्पादन लागत को अपनाए जाने का विरोध करते रहे हैं और वह कोरिया में आयात कीमत पर विचार करने और अधिप्रापण कीमत की अयथार्थता के मद्देनजर निर्यातक की उत्पादन लागत को अस्वीकार करने का अभिवचन करते रहे हैं। तथापि, कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने न तो घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत अंतर्राष्ट्रीय कीमत की राशि के संबंध में कोई टिप्पणी की और न ही सूचना के स्रोत की यथार्थता अथवा सूचना की परिशुद्धता के संबंध में ही कोई टिप्पणी की।

58. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस रिमांड कार्रवाई में एक बार फिर घरेलू उद्योग ने एक विवरण प्रदान किया जिसमें आईबीआईएस द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में 4एडीपीए के आयात को दर्शाया गया, इनमें भारत में 4एडीपीए के इन आयातों का सौदावार विवरण शामिल है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने आयात मात्रा अथवा आयात कीमत का निर्धारण करने के लिए आईबीआईएस को सूचना के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जर्मनी से भारत को 4एडीपीए के आयातों के आधार पर 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय आयात कीमत *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम के रूप में मूल जांच के समय भी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है। प्राधिकारी ने आईबीआईएस आंकड़ों की उपयुक्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और 4एडीपीए की कीमत *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम अपनाने के संबंध में कोई अशक्तता नहीं है।

59. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी से केपीसी के व्यक्तिगत लागत निर्धारण तत्वों का प्रकटन घरेलू उद्योग से किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमों में यह अपेक्षा है कि निर्धारण करते समय प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्योग ने लागत निर्धारण के विशिष्ट तत्व के संबंध में मुद्दा उठाया था इसलिए प्राधिकारी से उसका समाधान करने की अपेक्षा की

जाती है। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग के लागत निर्धारण अथवा गैर-क्षतिकारी कीमत तत्वों से संबंधित विशिष्ट मुद्दा उठाता तो प्राधिकारी द्वारा उन मुद्दों पर भी विचार किया गया होता और उनका भी समाधान किया जाता। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में गोपनीयता से संबंधित नियमों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है और, इसलिए हालांकि निर्यातक की विशिष्ट गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता है, तथापि प्राधिकारी ने निर्यात की उत्पाद लागत से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान कर दिया है।

60. जहां तक प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई सत्यापन रिपोर्ट और उन सत्यापन रिपोर्टों पर टिप्पणियों तथा स्थल सत्यापन के समय घरेलू उद्योग अथवा निर्यातक द्वारा प्रदान कराए गए दस्तावेजों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की यह संगत परम्परा रही है कि वह सत्यापन रिपोर्ट का प्रकटन घरेलू उद्योग को नहीं करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह सत्यापन रिपोर्टें पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुपालन में निर्यातकों को जारी की जाती हैं, जबकि भारतीय विधि के अंतर्गत ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है।

61. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे पर निर्यातक और आयातक टिप्पणियां नहीं करते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अगोपनीय प्रस्तुतिकरण हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन अगोपनीय पाठों में 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के संबंध में किए गए घरेलू उद्योग के दावों से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी शामिल हैं। आयातकों और निर्यातकों को अपने हितों की रक्षा करने और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों का प्रतिरोध करने का स्पष्ट अवसर होता है। तथापि, आयातक-निर्यातक ने उस पर अपनी कोई टिप्पणी न देने अथवा 4एडीपीए की कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कीमत न देने को अधिमानता दी है। आयातक के साथ-साथ निर्यातक का भी मुख्य बल यह था कि प्राधिकारी आयातक द्वारा प्रदान कराई गई उपभोग कीमत और इसकी लागत को निर्यातक द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

62. केपीसी की उत्पादन लागत का निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रदान कराई गई और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की गई सूचना पर विचार करते हुए किया गया है। निर्यातक द्वारा दावा किए गए व्ययों और लागत के सभी तत्वों की, निम्नलिखित को छोड़कर, अनुमति दी गई है :

- (क) 4एडीपीए की उपभोग लागत : प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई 4एडीपीए की उपभोग लागत को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी ने 4एडीपीए की आईबीआईएस द्वारा रिपोर्ट की गई उपभोग लागत को अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए ***यूएस डालर की सीआईएफ कीमत को अपनाया गया है। इसका समायोजन (क) चीन और कोरिया तथा जर्मनी और भारत के बीच भाड़े के अंतर; (ख) कोरिया में पत्तन व्यय; (ग) कोरिया में आयातों पर *** प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क; और (घ) कोरिया में पत्तन से केपीसी के कारखाने तक का अंतःस्थलीय भाड़ा के लिए किया गया है। इस तरह ग्रहण की गई उपभोग लागत *** यूएस डालर बनती है।
- (ख) ब्याज लागत : निर्यातक द्वारा दावा किए गए ब्याज व्ययों पर विचार निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई ब्याज आय का अपवर्जन करके किया गया है। ब्याज लागत की अनुमति ब्याज आय का समायोजन किए बिना की गई है।
- (ग) निर्यातक द्वारा दावा की उत्पादन/विक्री लागत *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम है जबकि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उत्पादन लागत *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पाद लागत का पूर्ण प्रकटन निर्यातक को गोपनीय आधार पर किया जा रहा है।
- (घ) चूंकि निर्यातक द्वारा की गई सभी विक्रियां प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उत्पादन लागत से कम पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण विक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा युक्तियुक्त लाभ को जोड़ने के पश्चात् उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

घ. पाटन का आकलन – क्रियापद्धति और प्राचल

कोरिया आरपी के लिए पाटन मार्जिन

1) कोरिया के लिए 6पीपीडी हेतु निर्धारित सामान्य मूल्य का ब्यौरा

63. प्राधिकारी ने 4एडीपीए की *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम की दर से लागत पर विचार किया है क्योंकि यह वह लागत है जिस पर एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश अर्थात् जर्मनी से उक्त कच्चे माल को प्राप्त किया गया था, यह घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए

आंकड़ों के आधार पर किया गया था। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 6.2.2008 के पत्र के साथ संलग्न विवरण में आईबीआईएस से प्राप्त *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम की उपर्युक्त कीमत को दर्शाया गया था।

64. प्राधिकारी ने *** केआरडब्ल्यू प्रति यूएस डालर की औसत विनिमय दर को अपनाया है और 4एडीपीए की *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम दर का निर्धारण किया है जबकि केकेपीसी द्वारा प्रस्तुत पारिशिष्ट 8ख में 4एडीपीए की *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम दर का दावा किया था।

65. उपर्युक्त के मद्देनजर, 6पीपीडी की उत्पादन लागत का पुनर्निर्धारण 4एडीपीए की उपभोग दर को *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम से संशोधित करके *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम पर विचार करते हुए तथा लागत के अन्य तत्वों में कोई भी परिवर्तन न करते हुए किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 6पीपीडी की लागत *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम से बढ़कर *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम हो गई।

66. चूंकि 6पीपीडी की *** केआरडब्ल्यू प्रति किलोग्राम की संशोधित लागत केकेपीसी की घरेलू विक्रियों के लिए घरेलू विक्री कीमत से अधिक है, इसलिए व्यापार का सामान्य अनुक्रम परीक्षण असफल हो गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने 6पीपीडी के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विक्री लागत के 5 प्रतिशत की दर पर लाभ पर विचार ब्याज का अपवर्जन करते हुए किया है। इस तरह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 6पीपीडी का सामान्य मूल्य *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम बनता है।

ii) केकेपीसी द्वारा भारत को निर्यातित 6पीपीडी के लिए निर्धारित निर्यात कीमत का विवरण

67. प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत का निर्धारण केकेपीसी द्वारा दायर पारिशिष्ट-2 के आधार पर उसका विधिवत सत्यापन करने के पश्चात् किया है। केकेपीसी द्वारा दावा किए गए समायोजनों अर्थात् अंतःस्थलीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा (टर्मिनल प्रहस्तन प्रभार, बिल आफ लैडिंग फी, प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क को शामिल करते हुए), सामुद्रिक बीमा, बैंक प्रभार और कमीशन को सत्यापित किया गया तथा उसे स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, 4एडीपीए की कीमत के संबंध में विचार किए गए संशोधित सीमाशुल्क के आधार पर भारत को निर्यातों पर प्राप्त शुल्क प्रतिअदायगी के लिए ऋणात्मक समायोजनों को भी स्वीकार कर लिया गया। इस तरह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 6पीपीडी की निवल निर्यात कीमत *** यूएस डालर प्रति किलोग्राम बैठती है।

कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी के लिए पाटन मार्जिन

68. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के उपर्युक्त परिकलनों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन अधोलिखित तालिका में दिया गया है।

सामान्य मूल्य यूएस डालर/ प्रति किग्रा.	निवल निर्यात कीमत यूएस डालर/ प्रति किग्रा.	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ प्रति किग्रा.	पाटन मार्जिन (प्रतिशत)	पाटन मार्जिन (प्रतिशत) रेंज
***	***	***	***	0 - 10

ड. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का आकलन

i) क्षति निर्धारण

69. प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पीएक्स-13 के आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों में यह भारी वृद्धि भारत में कुल आयात, उत्पादन और भारत में उपभोग के संबंध में हुई है। कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इन आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन हो रहा था और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान पहले तो सुधार हुआ और तत्पश्चात् उसमें उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में गिरावट आई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू विक्रियों और बाजार हिस्से में गिरावट आई तथा मालसूची में वृद्धि हुई। आयातों से घरेलू कीमतों का निग्रहण हो रहा था। चीन जन.गण. और कोरिया आरपी से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक था। इस प्रकार, संबद्ध वस्तु के पाटन से

घरेलू उद्योग को क्षति कारित की जा रही है और यह कि इस संबद्ध वस्तु के पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्षति मार्जिन	मापन की इकाई	जांच की अवधि
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/किग्रा.	***
कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड कोरिया आरपी का उतराई मूल्य	रुपए/किग्रा.	***
क्षति मार्जिन	रुपए/किग्रा.	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन रेंज	%	20-30

ii) कारणात्मकता के संबंध में निष्कर्ष

70. दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच-परिणाम और वर्तमान निर्धारण में की गई विस्तृत जांच के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ। इसके अतिरिक्त, आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत और आवेदक की संबद्ध वस्तु के निबल बिक्री प्रापण से कम थी। संबद्ध देशों से आयात ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित की जिसके कारण संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है। पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है जिससे घरेलू उद्योग को मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री में वृद्धि करने से वंचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में उस सीमा तक वृद्धि नहीं हुई जिस सीमा तक घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग कर सकता था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का परिणाम यह हुआ कि इसका घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा। पाटित आयातों द्वारा कारित किए गए भारी कीमत अधोरदन से घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में जांच की अवधि में गिरावट आई। भारी कीमत अधोरदन और पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन पर लाभ, नकदी प्रवाह एवं निवेश पर प्रतिलाभ पर भारी, विपरीत प्रभाव पड़ा, इन प्राचलों में वर्ष 2005-06 तक सुधार हुआ और फिर उसके पश्चात् जांच की अवधि में इसमें गिरावट आ गई।

71. इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि कोरिया और चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अभिप्राय: के अंतर्गत घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित की है।

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सेस्टैट ने अपने दिनांक 26.12.2014 के पत्र के तहत प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने तथा इस निर्णय के पश्चात् हुई सुनवाई के परिणामस्वरूप अंतिम जांच परिणाम में यथावश्यक संशोधन करने का निदेश दिया है।

73. इससे पहले अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम, जांच की कार्यवाई के दौरान तथा निर्णय पश्चात् मौखिक सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों और उसके पश्चात् दिए गए विभिन्न प्रति प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर विधिक दृष्टिकोण से तथा वास्तविक स्थिति के अनुरूप विचार करते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करने का प्रस्ताव करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा इससे पूर्व अधिसूचित किए गए अंतिम जांच परिणाम में, कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से संबंधित पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन करने के अलावा किसी तरह का अन्य संशोधन करना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात इससे जुड़े इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया। इस तरह कोरिया कुम्हो के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसलिए कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है।

ब. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात् किए गए अधिकांश प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण किए हैं, वह संक्षेप में अधोलिखित है:

- क. सेस्टैट आदेश के अनुसरण में रिमांड की कार्यवाही इसके दायरे से अधिक नहीं हो सकती है; माननीय सेस्टैट के समक्ष आवेदन घरेलू उत्पादक की अपील में किसी पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी गई थी। आवेदक घरेलू उत्पाद सेस्टैट के आदेश में ऐसा कोई वाक्स इंगित करने में अक्षम रहे जो यह अभिव्यक्त करता हो कि आवेदक घरेलू उत्पादक की अपील के अनुरूप पुनर्निर्धारण करने का कोई निदेश दिया गया था।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने खुद के आदेश की पुनरीक्षा नहीं कर सकते और आवेदक घरेलू उत्पाद के नए सन्निवेश एवं अन्वेषणों का तब समर्थन नहीं कर सकते जब उन्हें इस स्तर पर सीमाशुल्क का भुगतान करने और अन्य ऐसे ही बाह्य मुद्दे के बारे में पुनर्निर्धारण करने का अधिदेश न हो। पुनर्निर्धारण करने के निदेश का आशय केवल उन सभी पहलुओं का पुनर्निर्धारण करने से है जिनका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त 4एडीपीए की कीमतों का प्रकटन न किए जाने के कारण इससे पूर्व पुनर्निर्धारण न किया जा सका हो।
- ग. जहां तक केपीसी का संबंध है, केपीसी की अपील में किसी भी मुद्दे पर उसे उस स्थिति में वह उन मुद्दों पर अपील दायर करने से पहले था। माननीय सेस्टैट द्वारा यथा-संरचित मुद्दों से यह प्रकाश में आता है कि पुनर्निर्धारण से संबंधित एकमात्र मुद्दा यह था कि वह 4एडीपीए की प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का खुलासा केपीसी को करे और केपीसी द्वारा उस कीमत को अपनाने से संबंधित किसी भी मुद्दे पर केपीसी द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करे। यह विचार करने का मुद्दा कि क्या 4एडीपीए के आयातों पर सीमाशुल्क का भुगतान कर दिया गया है और उपचित किए गए अन्य खर्च, इन मुद्दों पर रिमांड के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारण करने के लिए मुक्त नहीं है।
- घ. यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि आवेदक घरेलू उत्पादक और निर्दिष्ट प्राधिकारी दोनों ही को अंगीकृत 4एडीपीए की कीमतों की जानकारी थी। आवेदक घरेलू उत्पादक ने किसी भी स्तर पर यह प्रस्तुतिकरण नहीं किया कि प्रतिस्थापन के लिए प्रयोग की गई कीमतों के संबंध में उन्हें अंधेरे में रखा गया। यहां तक कि आवेदक घरेलू उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का पूरा समर्थन किया। इसलिए, आवेदक घरेलू उत्पादक और निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए इन कीमतों का प्रयोग करने से पहले उनमें सीमाशुल्क अथवा किसी अन्य व्यय का समावेशन अथवा अपवर्जन करने की जानकारी थी।
- ङ. इन हालातों में यह एक स्पष्ट पूर्वधारण है कि यह सभी समायोजन जिनका अब आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा अनुरोध किया गया है उनका समायोजन पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यदि यह मान भी लिया जाए कि इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था और आवेदक घरेलू उत्पादक इन पहलुओं पर चुप रहा और अपील में इसको चुनौती न देकर अपने अधिकार का उसने पूर्वानुमान कर लिया, तो अब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तरह के समायोजन को पुनः स्वीकार करके आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा एक बार अपने अधिकार को छोड़ देने पर प्रतिवादियों की अपील में पुनर्निर्धारण के लिए निदेश के बहाने अब इस अधिकार को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह से पुनर्निर्धारण का निदेशक प्रतिबंधित है।
- च. यह पुनः दोहराया जाता है कि पैराग्राफ 27.ग में शब्द "सीआईएफ" का प्रयोग इरादतन किया गया है, हालांकि उसका इससे पूर्व प्रयोग नहीं किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निर्धारण में सीआईएफ कीमत/एफओबी कीमत पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं।
- छ. सीआईएफ की शुरुआत पाटन मार्जिन स्तर को बनाए रखने के लिए दावाकृत उतराई मूल्य में सीमाशुल्क को एक बार पुनः जोड़ने की दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए की गई थी।
- ज. इसके अतिरिक्त, जब आवेदक घरेलू उत्पादक ने पिछली बार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे तो यह प्रकल्पना नहीं की गई थी कि केपीसी का समुद्री प्रचालन सीमाशुल्क सीमाओं से परे है और इसलिए 4एडीपीए के आयातों पर सीमाशुल्क संदेय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह पूर्णतया स्पष्ट एवं संदेह से परे है कि आवेदक घरेलू उत्पादक को प्रतिस्थापन के लिए 4एडीपीए की कीमतों का प्रस्तुतिकरण भारत में उस समय संदेय सीमाशुल्क अर्थात् 15 प्रतिशत जोड़कर करना चाहिए था। आवेदक घरेलू उत्पादक और निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करने में असफल रहे कि किस कारण से यह समायोजन इससे पहले नहीं किए गए थे।

- झ. यदि आवेदक घरेलू उत्पादक दिनांक 01.10.2008 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने से पहले किसी भी समय पर सीमाशुल्क को शामिल करने से असफल रहे और तत्पश्चात् उसी पहलू पर अपील दायर करने से भी असफल रहे, इसलिए अब आवेदक उत्पादकों को इन दावों को स्वीकार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नवीन दावा करने का अधिकार नहीं है।
- ञ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 4एडीपीए की कीमतों को अपनाते समय शुल्क प्रतिअदायगी के संबंध में समायोजन प्रदान किया है और इसलिए युक्तियुक्त ढंग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि अंगीकृत कीमत में सीमाशुल्क के तत्व को पहले ही शामिल कर लिया गया है, तभी इस समायोजन की अनुमति दी जा सकती है।
- ट. आवेदक घरेलू उत्पादक को उसके द्वारा मांगे गए सभी समायोजनों की अनुमति दे दी गई, यद्यपि इन पहलुओं का मुद्दा न तो कभी उठाया गया और न ही इन पहलुओं के संबंध में कभी कोई अपील दायर की गई। प्रतिवादियों ने दिनांक 01.10.2008 के अंतिम जांच परिणाम में यह प्रदर्शित किया कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि साइनोगकिम द्वारा भारत को 4एडीपीए की कीमतें केपीसी को 4एडीपीए की कीमत की तुलना में काफी अधिक थीं। इस अंतर का मुख्य कारण मात्रा में अंतर होता है। उस अंतर की अनुमति नवसृजित प्रतिस्थापित कीमत के रूप में दी जानी चाहिए। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य पर पूर्ववर्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम की अनदेखी की गई है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए अधिकांश विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका इस प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात् किए गए प्रस्तुतिकरण, संक्षेप में, निम्नलिखित हैं:

- क. वर्तमान निर्णय पश्चात् कार्यवाही का दायरा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई क्रियापद्धति का प्रकटन करना है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी सेस्टेट के प्रेक्षकों के आलोक में सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सेस्टेट के निदेशों से परे नहीं जा सकते हैं।
- ख. घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वह सामान्य रूप से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने और विशेष रूप से ब्याज लागत, स्टीम लागत, एसजीए व्यय और ग्राही इनपुटों का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का प्रकटन करें।
- ग. घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वह या तो 4एडीपीए की लागत में आयात से जुड़े सीमाशुल्क और सभी व्ययों को जोड़े अथवा शुल्क प्रतिअदायगी के प्रति ऋणात्मक कटौतियों के समायोजन की अनुमति न दें।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरूप पाटन मार्जिन में समुचित रूप से संशोधन करे और उसके परिणामस्वरूप समायोजन करने के पश्चात् शुल्क प्रमात्रा में संशोधन करे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

76. निर्यातक की टिप्पणियों का मुख्य रूप से संबंध रिमांड जांच के दायरे से है। प्रकटन के पैरा 16 में किए गए उल्लेख के अनुसार न्यायाधिकरण ने 6पीपीडी का पुनर्निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन, जहां तक उनका संबंध कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स से है, का प्रकटन करने और उसकी क्रियापद्धति का प्रकटन करने के लिए निर्णय पश्चात् सुनवाई के दायरे को सीमित करते हुए विशिष्ट आदेश दिए हैं। संशोधित निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण न्यायाधिकरण के उपर्युक्त आदेशों के अनुरूप हैं। सभी टिप्पणियां निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस पुनर्निर्धारण के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में पर्याप्ततः उल्लेख किया गया है। परिकलन पत्र और क्रियापद्धति की निर्यातक के प्रतिनिधि के साथ विधिवत साझेदारी की गई है। परिकलनों के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां नहीं की गई हैं। उन्होंने केवल उसके दायरे को चुनौती दी है जिसमें कोई दम नहीं है।

ट. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हैं। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश/भू-भाग से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा, इसलिए, इससे उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

78. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित कर दिया जाए तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आई कमी को दूर करेगा, और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

79. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने; और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का भारत को कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद का पाटन हुआ। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के बारे में वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी। यह वास्तविक क्षति कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी से पाटित आयातों के कारण कारित की गई है।

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उद्योग, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की स्थापना करके प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है। इसलिए, प्राधिकारी कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तु के आयातों अधोलिखित स्वरूप और ढंग से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सेस्टेट ने यह मामला प्राधिकारी के पास ही इस निदेश के साथ रिमांड कर दिया कि प्राधिकारी ही कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी से संबंधित 6पीपीडी की निर्यात कीमत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के लिए पुनर्निर्धारण करे। प्राधिकारी ने कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायन 6पीपीडी (पीएक्स-13) के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश अपने दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी के तहत दिनांक 28 फरवरी, 2008 की अन्तिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/15/2007-डीजीएडी के अधिरोपण की तारीख से ही पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा इसका उदग्रहण 05 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 61/2008-सीमाशुल्क से प्रभावी दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 133/2008-कस्टम्स के तहत किया गया था। रिमांड मामले में प्राधिकारी ने कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी के लिए पाटन मार्जिन को दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 की मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी में की गई सिफारिश में परिवर्तन कर दिया।

82. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्रीय सरकार से यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 की अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 14/5/2007-डीजीएडी की शुल्क तालिका के क्रम संख्या 4 के कालम संख्या 9 में शुल्क की राशि में संशोधन करके उसे 10.35 के बजाय 5.90 के रूप में पढ़ा जाए और केंद्रीय सरकार से पुनः यह सिफारिश करते हैं कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर ऊपर विनिर्धारित राशि के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 05 मई, 2008 से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है। तथापि, ऊपर उल्लिखित संशोधित शुल्क का प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2011 की मध्यावधि समीक्षा अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/21/2010-डीजीएडी, तथा दिनांक 19 अगस्त, 2011 के शुद्धिपत्र और दिनांक 29 अप्रैल, 2014 की निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/1/2013-डीजीएडी में संस्तुत शुल्क की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

83. केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2015

(Final Findings)

Subject: - CESTAT remand case in the Final Findings issued in the anti-dumping investigation concerning the imports of Rubber Chemicals, namely, MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT originating in or exported from China PR and PX-13(6PPD) originating in or exported from China PR and Korea RP-reg

No.14/5/2007- DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules or AD Rules):

A. BACKGROUND

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), consequent to an application filed by National Organic Chemical Industries Ltd. on behalf of the domestic industry, had recommended imposition of anti dumping duty on the imports of Rubber Chemicals, namely, MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT originating in or exported from China PR and PX-13(6PPD) originating in or exported from China PR and Korea RP vide its Final Findings Notification No.14/5/2007- DGAD dated 1st October, 2008. On the basis of the Findings, anti dumping duties on the above mentioned rubber chemicals originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) were imposed by the Central Government vide Notification No.133/2008-Customs dated 12th December, 2008.
2. Aggrieved by the recommendations of the Authority in the above referred Final Findings, M/s Kumho Petrochemicals Co. Limited, Korea RP, a Korean exporter of one of the rubber chemicals, i.e., PX-13(6PPD) and M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., an Indian importer of PX-13(6PPD) filed appeals before the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter also referred to as CESTAT or the Tribunal), challenging the Customs Notification No. 133/2008-Customs dated 12th December, 2008 issued by the Ministry of Finance and the Final Findings Notification No.14/5/2007-DGAD dated 1st October, 2008 issued by the Designated Authority, and praying for setting aside the impugned customs notification and the Final Findings.
3. National Organic Chemical Industries Ltd (NOCIL), the domestic industry in this investigation, also filed an appeal before the CESTAT, Principal Bench, New Delhi, challenging the Final Findings Notification No.14/5/2007-DGAD dated 1st October, 2008 and the Customs Notification issued by the Ministry of Finance and seeking modification / enhancement of duties on the exports from Korea RP.
4. The Hon'ble CESTAT passed its final orders nos. 54808-54810/2014-CU(DB) on 26.12.2014 in Application Nos. AD/STAY/1085&1449/2009-CU(DB); Application Nos. AD/MISC/60369, 61349, 60370 & 61348/2009-CU(DB) and Appeal Nos AD/6,7&9/2009-CU(DB) filed by M/s Kumho Petrochemicals Co Ltd, Korea RP; National Organic Chemical Industries and Rishiroop Polymers Pvt Ltd vs Designated Authority and Another, under Section 9C of the Customs Tariff Act against the Final Findings Notification No. 14/5/2007-DGAD dated 01.10.2008 and the Customs Notification No. 133/2008-Customs dated 12th December, 2008 issued by the Central Government in the anti-dumping investigation concerning imports of Rubber Chemicals originating in or exported from China PR and Korea RP, remanding the matter back to the Designated Authority to grant post-decisional hearing to the concerned parties and complete other associated process preferably within six months from the date of the order.
5. The brief facts under consideration of the CESTAT in the said appeals were the Authority had recommended imposition of anti-dumping duty on the exports of, *inter-alia*, PX-13 (6PPD) from *inter-alia* M/s Kumho Petrochemicals Co. Ltd, Korea RP. The Authority found that the exports from Korea RP were being made below their normal value and the domestic industry had suffered material injury, cumulatively from the subject imports. In respect of the Korean exporter Kumho Petrochemicals, the Authority had constructed its cost of production for PX-13 (6PPD) (hereinafter also referred to as the subject goods), by considering the international price of the major raw material, i.e., 4-ADPA instead of the actual procurement cost of the said raw material from China PR.
6. The Id. counsel of the exporter Kumho Petrochemicals had inter-alia submitted to the Tribunal that the normal value for 6PPD had not been appropriately determined by the Designated Authority; that Kumho Petrochemicals had been sourcing 4ADPA from Sinorgchem, China PR and that the Authority committed a serious error by rejecting the actual cost of 4ADPA, in the absence of any legal provision to justify rejection of the actual cost of procurement of 4ADPA, since Korea is a market economy country and not subject to provisions of paragraphs 7 and 8 of

Annexure 1 to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

7. The Id. counsel for the domestic industry had inter-alia submitted to the Tribunal that the actual cost of procurement of 4-ADPA (the main raw material to manufacture 6PPD) from Sinorgchem from China was not reliable since it did not reflect the intrinsic cost of the input.
8. The Id. counsel for the Authority had inter-alia contended that since 4ADPA used in production of 6PPD was solely sourced from China, a non-market economy company, the use of actual purchase price of Kumho Petrochemicals for 4ADPA would not reasonably reflect the cost associated with production of 6PPD. The Authority had correctly revised the cost of sales of 6PPD. On the aspect of inadequate disclosure, it was argued that the international market price was given in paragraph 58 of the Final Findings as USD 3.09 per Kg, as also in the letters of domestic industry, which were available in the public file. It was also argued that the methodology adopted for fixation of normal value and export price had been appropriately given in the disclosure statement.
9. The Id. counsel for the Department of Revenue supported the Notification on the ground that it was based on valid legal considerations and referred to the Panel Reports on the point that where the accounts do not appropriately reflect the intrinsic value of an input, the Authority was justified in adoption of international price.
10. In the context of the aforesaid arguments, the Tribunal framed the following issues for its consideration :-
 - i) Whether the Authority was right in construction of the cost of production of 6PPD, disregarding the cost of 4ADPA.
 - ii) Whether due process has been followed by the Designated Authority with regard to disclosure of relevant information to the affected parties.
11. In the light of the foregoing, the Hon'ble Tribunal passed the final orders as under:

Findings and order

20. In the light of the foregoing, we are of the view that the Authority rightly rejected the price of 4ADPA from Sinorgchem, and opted for construction of normal value, based on the international price of 4ADPA. However, having rightly rejected the 4ADPA price from China and opting for construction of normal value based on the international price of 4ADPA, it was incumbent on the Authority to make adequate disclosure, and call for information / comments from the interested parties as regards evidence of international price. We find that the domestic industry had brought on record evidence of the import prices of 4ADPA from Germany to India. But the Authority before recording the Final Findings, did not give opportunity to the other interested parties, to comment on acceptability / appropriateness of such evidence. To this extent, the Authority has not observed due process and violated the principles of natural justice and adversely affected the rights of the Korean exporter. We also find merit in the submission of domestic industry, that the methodology followed for fixation of export price, normal value, and dumping margin has not been given in sufficient detail, to enable them to offer meaningful comments. The Apex Court in the case of Automotive Tyre Manufacturers Association [2012 (263) 481 (SC)] in the context of anti-dumping case has held as under:-

“58. It is thus, well settled that unless a statutory provision, either specifically or by necessary implication excludes the application of principles of natural justice, because in that event the Court would not ignore the legislative mandate, the requirement of giving reasonable opportunity of being heard before an order is made, is generally read into the provisions of a statute, particularly when the order has adverse civil consequences which obviously cover infraction of property, personal rights and material deprivations for the party affected. The principle holds good irrespective of whether the power conferred on a statutory body or Tribunal is administrative or quasi-judicial. It is equally trite that the concept of natural justice can neither be put in a strait-jacket nor is it a general rule of universal application. Undoubtedly, there can be exceptions to the said doctrine. As stated above, the question whether the principle has to be applied or not is to be considered bearing in mind the express language and the basic scheme of the provision conferring the power; the nature of the power conferred and the purpose for which the power is conferred and the final effect of the exercise of that power. It is only upon a consideration of these matters that the question of application of the said principle can be properly determined. [See: Union of India v. Col. J.N. Sinha & Anr. (1970) 2 SCC 458]

59. In the light of the afore noted legal position and the elaborate procedure prescribed in Rule 6 of 1995 Rules, which the DA is obliged to adhere to while conducting investigations, we are convinced that duty to follow the principles of natural justice is implicit in the exercise of power conferred on him under the said Rules.”

21. We, therefore, direct the Designated Authority to make disclosure of the international price of 4ADPA adopted by the Authority as well as the methodology used for fixation of normal value, export

price and dumping margin. The Designated Authority shall grant post-decisional hearing to the parties and re-determine for 6PPD the export price, normal value, and the dumping margin in the light of the observations made above, in so far as they relate to Kumho Petrochemicals. The respondent-domestic industry and other interested parties, if any, shall also be allowed to participate in such post-decisional hearing. Any modifications thus made in the Final Findings would be considered by the Government for the purpose of amending the impugned anti-dumping notification. This process shall be completed expeditiously, *preferably* within 6 months from the date of this order. Status quo shall be maintained in the meanwhile”.

B. PROCEDURE

12. The procedure described below has been followed in this investigation:

- a. In compliance with the order of the Hon'ble CESTAT, the Authority vide email dated 1st April, 2015 provided to the interested parties the import price of raw material 4-ADPA from Germany to India which the domestic industry had brought on record as evidence and which was adopted by the Authority for computation of normal value of Korea RP.
- b. In compliance with the order of the Hon'ble CESTAT, the Authority vide email dated 1st April, 2015 also provided to all the interested parties the methodology of calculation of normal value and export price.
- c. The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a Oral Hearing held on 24th April, 2015. The oral hearing was attended by the following parties: National Organic Chemical Industries Ltd. (NOCIL), the Domestic Industry, M/s Kumho Petrochemicals Co. Ltd., Korea RP (exporter) and Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. (importer).
- d. The interested parties who presented their views orally at the time of Oral Hearing were requested to file written submissions of the views expressed by them orally and were allowed to file rejoinders to the submissions made by the opposing parties. The following interested parties filed submissions subsequent to the oral hearing:
 - NOCIL- Domestic Industry
 - M/s Kumho Petrochemicals Ltd., Korea RP and
 - M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai
- e. Submissions made by various interested parties pursuant to the post decisional oral hearing held by the Authority were examined in detail in the light of the facts and the legal provisions.
- f. After the oral hearing, a Disclosure Statement was issued on 03.08.2015. However, because of a sudden administrative exigency, a new officer was appointed as the Designated Authority. This development necessitated that a new public hearing be held by the new DA as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) vs Designated Authority, delivered by a Division Bench in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7-1-2011. The new oral hearing was, therefore, conducted by the new Designated Authority on 28.08.2015. All the interested parties who attended the hearing were again requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally. The following interested parties filed submissions subsequent to the second oral hearing:
 - NOCIL- Domestic Industry,
 - M/s Kumho Petrochemicals Ltd., Korea RP, and
 - M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai
- g. After the second oral hearing, second Disclosure Statement was issued on 06.10.2015. The submissions subsequent to the second Disclosure Statement were filed on behalf of the same interested parties and the domestic industry, which have been considered to the extent found relevant to the investigation.
- h. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority on merits under the Rules.
- i. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.53.69 = 1US\$.

C. SUBMISSIONS MADE AFTER POST-DECISIONAL ORAL HEARINGS

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

13. The following submissions were made by the domestic industry:

- a. The CESTAT has upheld the decision of the Authority to reject the price of 4ADPA and adoption of constructed normal value based on international price. The issue is now beyond the scope of the present post decisional hearing. The only scope of the present post decisional proceedings is to disclose the international price and methodology adopted for fixation of normal value, export price and dumping margin. Further the Designated Authority may re-determine normal value, export price and dumping margin in the light of the CESTAT observation.
- b. No disclosure relating to methodology adopted for determination relating to constructing cost of production of KKPC was provided to the domestic industry, including copies of verification report, etc. Verification report issued to KKPC and comments offered by KKPC on the verification report formed the basis for the methodology adopted and determination of dumping margin and, therefore, its disclosure was extremely important and relevant for the domestic industry. The domestic industry has sought disclosure of the same.
- c. Manner of computation of interest cost for the determination of normal value has not been disclosed to the domestic industry, including the issue that interest income not relating to the product under consideration cannot be set off against interest expenses relating to the product.
- d. Steam is generally not a marketable commodity and thus determination of its cost has always been disputed. Therefore, reduction of the cost of production by notional income from use of steam for other products is not permissible.
- e. The company claims SGA expenses, which are not strictly on turnover basis. A number of adjustments are made by the company, which has not been admitted by the Designated Authority in the past. These adjustments are grossly shadowing the vital information of the company from the Authority.
- f. It is unclear as to how the company has priced its captive inputs. Any captively produced input should be charged to product at the prevailing market rates.
- g. Negative deduction (addition) has been made towards input drawback even though customs (import) duties have not been included in construction of 4ADPA cost. Thus, Authority allowed customs duty benefit in export price, without adding the same to the cost of production.
- h. For constructing cost of production of KKPC, the Designated Authority was required to include following expenses that would have been incurred by KKPC - (i) port expenses, (ii) clearing expenses, (iii) customs duty and (iv) inland freight from Korean port to factory.
- i. Though the Authority has disclosed the “methodology” adopted for calculation of normal value, export price and dumping margin, yet it is still to disclose the requisite information as sought by the domestic industry despite clear directions by CESTAT.
- j. Cost of production claimed by Kumho is understated and is required to be examined especially concerning costs on account of Steam, Interest Cost, SGA expenses, captive inputs, etc.
- k. The Korean exporter, Indian importers and consumers of the product under consideration never disputed this claim of domestic industry with regard to its accuracy and adequacy. The comments of these interested parties were limited only to appropriateness. Therefore, the question of accuracy and adequacy is no longer open to discussions.
- l. In spite of adequate time and opportunity, neither the Korean exporter nor the Indian importer has furnished an iota of evidence to controvert the evidence of international prices of 4ADPA submitted by the domestic industry in 2008. In the absence of alternate evidence being adduced by the exporter or any other interested party, the Authority is required to make a determination based on the information available on its record.
- m. The domestic industry had claimed a price of US\$ 3.09 and disclosed that this was based on IBIS data. While the interested parties had a right to claim that the Authority should adopt their records and consumption price as per their records, these interested parties had an obligation to claim before the Authority that the figures of US\$ 3.09 or the source based on which this figure was adopted was inappropriate.
- n. The interested parties neither demanded transaction wise information nor said that the figures claimed based on IBIS may be unreliable. The interested parties cannot reduce this post decisional hearing to a fact finding investigation, a job that is performed by the Authority at the time of original investigation. No methodology is required to be applied to sort out the data. 4-ADPA is imported by known names and all those transactions wherein the description is stated so must be considered.
- o. There is no obligation on the Authority to seek information from the Indian embassies or various ports. It is for the interested parties participating in the investigations to provide relevant information to the Authority. The Authority is required to make determination on the basis of information and submissions on record.
- p. The Authority in the past has adopted import data procured from private agencies apart from DGCI&S in a number of cases. The Authority has in the past discarded DGCI&S data and adopted IBIS or other secondary source data. Hence, it cannot be said that IBIS data adopted in the present case is not reliable unless evidence to the same is being provided to the Authority.
- q. The exporter may be called upon to demonstrate the manner and extent to which the factors like payment terms, delivery terms, freight, etc. would affect the price for the purpose of making the adjustment. It is submitted that such adjustment is permissible only where the exporter adduces evidence to show the effect of such factors on prices. Further adjustments on account of port expenses, custom duty, inland freight from Korea to factory etc also needs to be done.

- r. The Customs Valuation Rules and the Special Valuation Branch of the Customs Department implementing such Rules routinely reject the declared values, if they find that the relationship has influenced the price. The values being accepted by the customs authorities cannot be doubted at this stage.
- s. No evidence has been made available to the Authority to show the freight rates as they existed during the relevant period for different destinations. The freight rates are largely dependent on the volume of trade between different ports, rather than the distance alone.
- t. The exporter incurs expenses on account of port expenses, customs duty in Korea @ 6.5% and inland freight from Korean port to factory. The Authority should have considered the inland freight claimed by the exporter for exporting the product from Korea.
- u. If price of 4ADPA is adopted, the difference in manufacturing process has no relevance. Alleged difference in the process can at best have difference in the cost of production. No such adjustments have been made with regard to different manufacturing process of the raw material, when the eventual product or for that matter the raw material is competing in the same market in the past cases.
- v. As regards the argument that PMC Rubber Chemicals Ltd is also buying raw material from China at competing prices, the issue is beyond the scope of Post Decisional Hearing as read in the light of para 20 of the CESTAT judgment.
- w. There is no basis for the argument that if the volumes are higher the price shall be lower. In fact, it is a routine business situation that the price under contracts can be higher than the price in spot purchases (and vice versa).
- x. The interested parties had full opportunity to assist the Authority with documents and evidences and could have raised claims before the Authority at the time of original investigation. The interested parties can not reduce this post decisional hearing to a fact finding investigation process.
- y. As regards the argument of difference in exchange rate, it is factually incorrect and the average exchange rate table has been provided by the domestic industry to the Authority to verify its claim.
- z. There is no concrete evidence to disprove the claim of the domestic industry as the claims of the other interested parties hold no ground before the CESTAT order.
- aa. Additional time for completion of investigation has not caused any prejudice to any party, as the anti dumping duty imposed pursuant to the impugned notification has already completed its life long back and the fresh duty is running as a result of sunset review conducted by the Authority.
- bb. Once the Tribunal has held that the Designated Authority shall re-determine dumping margin, it follows that the Designated Authority is required to consider all relevant aspects thereof.
- cc. The price adopted was a CIF price and, therefore, reference to the same makes it obvious/clear to all the parties that the Designated Authority has adopted a CIF import price.
- dd. The price adopted by the Authority does not include customs duty payable in India and, therefore, it cannot be reduced again. The petitioner domestic industry did not claim international price of 4 ADPA on the basis of consumption price in India. The Authority can adopt this consumption price and add customs duties and all expenses associated with import in 4ADPA costs. The Authority is requested to consider this consumption price and determine dumping margin accordingly.
- ee. The price from Germany to India is unaffected by relationship. In fact, the customs have a clear provision for assessment of goods when transactions are between related parties. Even if such a provision exists in Korea, the transaction between Sinorgchem and KPC would not have been subjected to this scrutiny, given that they do not have relationship within the meaning of related party under the customs law. Notwithstanding, petitioner had made alternate claim of the consideration of cost of production of 4ADPA reported by the petitioner.
- ff. The port expenses are never added in the prices reported in the customs duty.
- gg. Customs data is in fact considered as an independent data. In fact, even the WTO Agreement provides that the Authority can consider customs data as best available information. Thus, there is no need for further verification of the same.
- hh. There is no legal requirement of providing excel sheets containing calculations.

C.2 Submissions made by the opposing interested parties

14. The following submissions were made by the opposing interested parties:

- a. The CESTAT order has been overruled by the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. No. 744/2015 in SanDisk International vs. The Designated Authority and others; wherein this CESTAT order was cited before the Hon'ble court but the court rejected the contention in toto and pronounced that in view of gross violation of principles of natural justice, the Final Findings cannot sustain or be remanded back to the Designated Authority.
- b. The Authority's obligation with regard to evidence collected from secondary sources not met. In view of the CESTAT decision, the Designated Authority was asked to make adequate disclosure, and call for information/comments from the interested parties as regards the evidence of international price.
- c. Import data of 4ADPA by domestic industry has following problems:
 - i. The raw data was never provided to the Authority by the domestic industry and in the absence of such data, Authority did not verify accuracy and adequacy of information.

- ii. Raw data as well as refined data was required to be disclosed to respondents.
- iii. Methodology adopted for sorting the raw data was not provided.
- iv. Since Authority has adopted the prices of 4ADPA without verification, the entire purpose is defeated and there is violation of principles of natural justice as well as Article 6.8 of ADA.
- v. The respondent is not aware if the Authority in the past has relied upon and adopted the other facts/figures submitted by domestic industry without verifying and substantiating the same.
- vi. The Authority should demonstrate that it has written to customs authorities at various ports, DGCI&S, Indian Embassies in the world to ascertain the international price for 4ADPA.
- d. The obligation to conduct the investigation is with the Authority and it is not the prerogative of the domestic industry to partially conduct the investigation. It is imperative on the part of Designated Authority to provide raw import statistics to the Respondent, if it is procured by the domestic industry. In a scenario, where the raw material has been sourced by the domestic industry, then it is even more imperative that the Authority seeks such data and independently corroborates the accuracy of such data.
- e. The Authority in the past has rejected the data on being deficient when it is procured from private agencies like IBIS/CYBEX/INFODRIVE found to be deficient and disregarded. Example is the USB Flash Drive case.
- f. It is vital that raw import statistics be provided to the interested parties to confirm:
 - a. imports statistics include only 4ADPA.
 - b. to check the quantities of imports so that very high or low quantities are not considered.
 - c. payment terms and delivery terms are verified and adjusted accordingly.
 - d. Freight element is required to be examined.
- g. To the best of the understanding, at that point in time Lanxess, Germany was the only producer of 4ADPA and its related company in India seems to have imported 4ADPA. The Authority is required to examine the following:
 - i. The price cannot be reflected of market price as these were transactions between related parties. No evidence to prove otherwise. The Customs Authority would not raise any doubts as they are getting higher customs duties on such high transaction values.
 - ii. The CIF price from Germany, a market economy third country, to India cannot easily substitute 4ADPA price from Sinorgchem to KPC as it includes freight from Germany to India and not from China to Korea, as the difference in distance is more than 15 times.
 - iii. The Authority has given adjustment to freight in sunset review and thus it may reconsider adjusting freight as well.
 - iv. The manufacturing process by Sinorgchem and by Flexsys is different. Therefore, the cost of producing 4ADPA will differ substantially. The Authority is required to give adjustments due to difference in production process.
- h. It is apparent that the basis of such summary was not provided by the Domestic Industry to the Designated Authority. The transaction-wise import statistics from which this summary would have been prepared was not provided even to the Designated Authority and the Designated Authority relied upon and adopted such unsubstantiated summary as evidence and anti-dumping duty was imposed.
- i. It is also apparent that the Designated Authority was never in possession of any other data/evidence to establish that the transaction value at which KPC procured 4ADPA was lower or unreliable.
- j. Further, the Designated Authority has never validated/verified by any means the data submitted by the Domestic Industry as a summary.
- k. If the assumption is made that the export price from China PR is always low and transaction value is unreliable because China is an NME, then in all cases at the time of assessment of goods in India imported from China the transaction value would be rejected and loaded/enhanced to arrive at the Assessable Value and higher import duties would be charged. However, such action would be based only on surmises and conjunctures and would not stand in the court of law.
- l. The Designated Authority is requested to make available other evidences, if any, regarding price of 4ADPA proposed to be used.
- m. The Designated Authority is requested to disclose other instances in the subject investigation where the Designated Authority has just relied upon and adopted the facts/figures submitted by the Domestic Industry without verifying and substantiating those facts and figures. The Designated Authority is requested to rely upon and adopt any fact/figure submitted by the Domestic Industry only after verifying and substantiate the same.
- n. If PMC Rubber Chemicals Ltd. is also buying raw material from China at competing prices, rejection of import price of the same by KPC is unjustified.
- o. The Authority could have adopted the price of China origin after seeking information from Customs regarding PMC import price from unrelated producer to KPC or Sinorgchem.
- p. KPC has purchased large quantities of 4-ADPA from Sinorgchem during the POI and accordingly the Authority is required to grant an adjustment for volume discount.
- q. Different exchange rate adopted for (i) import price of 4ADPA from China to India (ii) import price of 4ADPA from Germany to India and (iii) the average import price into India. The exchange rate adopted should be the same. This highlights the importance of providing raw data.

- r. The Authority considered the profits earned on the sales of subject goods as a whole including profits of export sales as well. The Authority should either consider profit margin for domestic sales or 5% as per consistent practice as adopted in sunset reviews.
- s. CESTAT has indeed held that the Authority was correct in rejecting the price of 4ADPA but that decision was made on the assumption that there is a reliable international price in existence.
- t. CESTAT has held that the Authority was correct in rejecting the price of 4ADPA from Sinorgchem and opting for construction of normal value based on international price of 4ADPA. However, the domestic industry has erroneously concluded that the Authority cannot go into the question of correctness of adoption of international price and rejection of 4ADPA price of Sinorgchem, as CESTAT arrived at such a conclusion on an assumption of reliable international price in existence.
- u. This price adopted by the Authority is unreliable primarily because such price involves sales between Lanxess Germany and Lanxess India who are related parties. Thus, this price is unreliable and must not be adopted. Considering the fact that there is no reliable international price of 4ADPA, the Authority must adopt price of 4ADPA from Sinorgchem itself.
- v. The Authority is required to follow same practice for disclosure of methodology for construction of normal value to domestic industry as it does for disclosure of methodology for determination of NIP to exporters. The CESTAT order nowhere mandates that individual costing element of KPC is required to be disclosed. Such information is confidential in nature and thus such disclosure is outside the scope of CESTAT order.
- w. In all past investigations, Authority only highlights the principles of determination of NIP to the exporters; it does not reveal each and every element of calculation while computing NIP. Likewise, only the principles of determination of normal value must be disclosed and not each and every calculation made while computing such normal value.
- x. The Authority is required to disclose the international price of 4-ADPA and receive and consider comments from interested parties on the suitability of such price used by the Authority and the Authority is required to disclose the methodology adopted for finalizing of normal value, export price and dumping margin and taking into account the comments of interested parties re-determine normal value, export price and dumping margin.
- y. The Authority must disclose the methodology used for fixation of normal value, export price and dumping margin and does not require to disclose individual costing element of KPC as it is confidential in nature and disclosure of such information is beyond the scope of CESTAT order and AD rules. The Authority must adopt the same standards of disclosure for all interested parties in an investigation.
- z. Verification reports and verification exhibits of the KPC are confidential information and cannot be disclosed to the domestic industry. Domestic Industry is trying to access KPC's confidential information under the guise of Rule 16 and if such verification reports and verification exhibits are to be disclosed then it must happen for both the parties.
- aa. The Authority has verified the costing information of KPC during the on the spot verification and is completely satisfied by the veracity of information.
- bb. Without identifying any specific instances where the allegation relating to interest cost has actually happened, respondents cannot make meaningful comments on the same.
- cc. Domestic industry is requested to clarify under which accounting rule captive inputs are valued at market rates. While determining cost of production, actual cost incurred by the exporter is to be ascertained.
- dd. Hon'ble CESTAT noted the submission of domestic industry of duty drawback but made no finding on this subject which shows that Hon'ble CESTAT feels there is no need to look into this aspect.
- ee. Hon'ble CESTAT has noted in its order that: "9. In respect of the appeal filed by domestic industry, it was argued that the import price of 6PPD into Korea may be considered for determination of Normal value. However, since the notification under challenge had already expired, they did not press this point at this stage".
- ff. The reason that respondent did not dispute the claim of domestic industry with regard to international price of 4-ADPA was because no disclosure about the international price of 4-ADPA adopted by the Authority for construction of normal value by KPC was ever made to the respondent during the original investigation and, therefore, there was no opportunity to make any comments on the same and this is the reason why the respondents went to appeal in CESTAT.
- gg. KPC has correctly disclosed all information which was substantially verified by the Authority and the Authority was satisfied with its accuracy. Since the Authority was satisfied with the costing records of the respondent, domestic industry's attempt to rake up this issue must be out rightly rejected.
- hh. Remand proceeding were directed by the Hon'ble CESTAT to be completed within 6 months from the date of the order. However, more than 6 months have passed from the date of order of CESTAT and the Authority is not able to complete the remand proceedings. The word used "preferably" in the CESTAT order does not mean that the proceedings would be commenced "preferably" at the far end of the six months.
- ii. The goods were non-dumped and consequently any continuation or extension of duty in the subsequent reviews was also illegal. Therefore, the proper determination of dumping margin for KPC in this proceeding would have far reaching consequences.
- jj. The Tribunal remanded the case only to the extent that the Designated Authority shall disclose the international prices which are proposed to be substituted for actual procurement cost of 4-ADPA by KPC and then after considering the comments of the Respondents (KPC), re-determine the dumping margin.

- kk. As far as other adjustment in freight, handling charges and customs duty are concerned, these adjustment are done incorrectly because:
- i. As the Applicant Domestic Producer never raised the issue of such expenses before the Designated Authority or in the Appeal before the Tribunal, they are debarred to raise such issue in remand proceedings, even if the Applicant Domestic Producer failed to include the customs duty at that point .
 - ii. Even the issue of duty-drawback is absent in the appeal and, thus, cannot be agitated by them in this remand proceedings
 - iii. The Designated Authority is also not empowered to review such issue in remand proceedings. KPC cannot be put into worst condition to the one they were before filing the appeal.
 - iv. The Applicant Domestic Producer, which provided the international price and which the Designated Authority adopted, must have added such expenses (15% customs duty payable in India plus freight and handling charges) and, therefore, firstly, such expenses are required to be deducted and then only comparable expenses may be added again.
- ll. The Designated Authority in its first Disclosure Statement has introduced the word “CIF” for the first time as the same was not appearing in the Final Findings which was remanded back. It has been introduced to overcome the difficulty to make an addition of the customs duty in the claimed landed value so as to once again to keep the dumping margin level as determined earlier
- mm. Since the 4ADPA price as submitted by the Applicant included customs duty @15%, it is the requirement to first deduct duty from the price to make a fresh claim before the Designated Authority to accept such claim.
- nn. The Applicant claimed for the substitution of consumption price of KPC. It is but obvious that the price submitted for the substitution by the Applicant would have been adjusted for all such expenses. Applicant never raised such issues before the Designated Authority before issuance of the Final Finding dated 01.10.2008 or subsequently in its appeal before the Tribunal that such adjustments are to be carried out. Thus, it is not anymore open at this stage to raise the issue.
- oo. Designated Authority is not supposed to review its final finding dated 01.10.2008 on the issue of completeness and correctness of the response to the questionnaire filed by KPC. Hon’ble CESTAT has not allowed the Designated Authority to do so. However, Designated Authority notes that KPC failed to provide breakdown of inland transportation and overseas transportation. It is not permissible for an Authority to review its own order suo-moto and hold against a party in a matter remanded to it on the appeal of such party, so that earlier order may be justified in any manner. Secondly there is no questionnaire format prescribed by the Authority that such breakup for transportation cost is required to be provided.
- pp. The supplier from Germany of 4-ADPA and buyers in India are related parties unlike KPC and Sinorgchem and, therefore, credit terms are required to be examined to allow necessary adjustment. Designated Authority cannot ignore “facts available” arbitrarily.
- qq. The Authority has not provided any reason as to why its previous decision with regard to interest expenses was wrong. In any case, as aforementioned, the respondents cannot be made worse off by the re-determining issues which are not open before the Authority pursuant to the remand order.
- rr. In the Final Finding date 01.10.2008, it is an admitted position that price of 4 ADPA to India by Sinorgchem was higher than the price of 4ADPA to KPC. The reason for the difference was the quantity discount. This fact on record cannot be ignored. The same difference should be allowed as adjustment to the newly subsisted price of 4-ADPA.
- ss. Designated Authority should disclose basis for arriving at the stated expenses for the port in Korea:
- i. Only the transaction-wise import data was made available. That data does not show if the value is assessable value or the value arrived at after adjusting other expenses. Therefore, it should be assumed that the value includes all adjustments
 - ii. Data in column below Importer (Column F) shows “company not known”. However, on top of the Excel File, it shows “Lanxes”. It is not known whether Lanxes provided such data or IBIS provided the same. In any case, the data also included import from China PR. The Hon’ble Tribunal already held that in case if imports of raw material are made from China, then that must be included in constructing the Normal Value, the Final Findings be modified to that extent.
 - iii. Value indicated in that data is the value at which goods are cleared by the customs at that time. Such value need not necessarily be the final assessment of imports by the Customs Authority. Goods can be cleared on a provisional assessment basis owing to several issues with regards to related party transactions in the instant case. The Designated Authority ought to provide the clarification in this regard.
 - iv. As regards the argument that goods can be cleared on a provisional assessment basis owing to several issues with regard to related party transactions in the instant case, the Authority notes that the interested parties have not provided any evidence to support their claim.
 - v. It is not clear whether the Designated Authority independently verified through any means the correctness of the imports of 4ADPA submitted by the Applicant Domestic Producer.

- tt. The Authority should have provided the calculations in excel sheet clearly containing the calculations methodology and the explanation used to arrive at the stated dumping margin. The Respondents are unable to make comment on the basis of hard copy.

C.3 Examination by the Authority

15. Whereas in the impugned customs notification and the Final Findings, the products under consideration were various Rubber Chemicals, viz., MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT originating in or exported from China PR and PX-13(6PPD) originating in or exported from China PR and Korea RP, the Tribunal limited the scope in the impugned appeals to only imports of PX-13 (6PPD) originating in or exported from Korea RP. Therefore, the scope of the present post decisional investigation is limited to imports of PX-13 (6PPD) originating in or exported from Korea RP. PX-13 (6PPD) is a rubber chemical having chemical description N-(1,3-dimethyl butyl)-N'' Phenyl-P-1 with other trade/brand names as 6C, Pilflex 13, Sirantox 4020 Antioxidant 4020, Kumhonax 13 Vulcanox 4020, etc.
16. The Authority notes that while remanding the matter back to the Authority, the Tribunal passed specific orders limiting the scope of the post decisional hearing and the scope of the re-determination in this remand investigation to the following:
 - a. Disclosure of international price of 4ADPA adopted by the Authority for re-determination for 6PPD the export price, normal value, and the dumping margin in so far as they relate to Kumho Petrochemicals.
 - b. Disclosure of "methodology" followed for fixation of normal value, export price and dumping margin.
17. The Authority, therefore, proposes to conclude that the scope of the present post decisional hearing and re-determination does not exceed beyond the issues mentioned in the preceding paragraph.
18. As far as the contention that the CESTAT order dated 26.12.2014 passed in the present remand case has been overruled by the Delhi High Court in the W.P. No 744/2015, it is noted that the Delhi High Court judgment is specific to the SanDisk case and cannot be said to have any bearing on the CESTAT order in the sense that the CESTAT order has not been stayed by the Delhi High Court.
19. The Authority further notes that Special Leave Petitions were also filed by Kumho Petrochemicals Ltd, Korea RP (KPC), Rishiroop Polymers and NOCIL, the Domestic Industry, against the CESTAT order dated 26.12.2014.
20. The Authority further notes that KPC and Rishiroop Polymers in their Special Leave to Appeal (C) No(s).12086-12087/2015 contended inter-alia that the above-mentioned order of CESTAT remanding the matter back to the Authority for re-determination was illegal and the findings should have been set aside. KPC and Rishiroop Polymers contended that the principles of natural justice have been violated and the post decisional hearing is not an appropriate remedy as much time has elapsed since the customs notification levying the anti dumping duty came into force. It was also contended by them that the major submissions of the interested parties were not taken into consideration by the CESTAT which rejected majority of their arguments. They also contended that the cost of production was not an evaluated fair cost and that the prices of exported goods are not low due to dumping. It was also argued that the determination of normal value by the Authority was incorrect.
21. The domestic industry on the other hand in its S.L.P.(C).CC No. 8088/2015 contended that the international price of 4ADPA was not rebutted by the Korean exporter and that they had enough time to comment on any discrepancy in the determination of the same and thus they had no merit in this contention. This fact was overlooked by the CESTAT and thus the case was remanded back to the Authority. It was contended by the domestic industry that the CESTAT did not appreciate the fact that KPC pleaded ignorance of the figures adopted by Authority and only pretended that there is gross violation of natural justice principles.
22. All these three SLPs came up for hearing on 8th May, 2015 wherein, after hearing the parties, the Hon'ble Supreme Court declined to grant leave to the parties and permitted withdrawal of their petitions. The Hon'ble court observed as follows:

"Learned counsel for the petitioners, on instructions, seeks permission of this Court to withdraw these special leave petitions with liberty to the petitioners, if they so desire, to question the correctness or otherwise of the order that may be passed by the designated authority, Director General of Anti-Dumping and allied duties, before an appropriate forum by taking up all such contentions which are available to them including the contentions raised in these special leave petitions. Permission sought for is granted".
23. Thus, the Hon'ble apex court disposed off the SLPs and they stand withdrawn with the aforesaid liberty.
24. It is, thus, noted that Hon'ble Supreme Court has neither held that the order of Hon'ble Tribunal remanding the matter back to the Authority for re-determination is inappropriate nor the Hon'ble Apex Court has held that the Tribunal should not have remanded the matter back to the Authority.

25. As regards the argument of delay in remand proceedings, the Authority had already issued the Disclosure Statement on 3rd Aug, 2015, but had to conduct the second oral hearing because due to a sudden administrative exigency, a new officer was appointed as the Designated Authority. Because of this development, as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) vs Designated Authority in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7-1-2011, the new Designated Authority has held second oral hearing on 23.08.2015.
26. As regards the argument that goods from KPC were undumped and consequently any continuation or extension of duty in subsequent reviews was also illegal, the Authority finds that the dumping margin was more than de-minimis limits prescribed.
27. The Authority notes that while remanding the matter back to the Authority, the Tribunal has ordered that the Authority shall re-determine the dumping margin. Therefore, the scope of the present investigation is re-determination of dumping margin in so far as it relates to Kumho Petrochemicals.
28. As regards the argument that the Authority is not empowered to review issues of adjustment in freight, handling charges and customs duty in remand proceedings, the Authority notes that the Authority is required to re-determine export price, normal value, and the dumping margin in so far as they relate to Kumho Petrochemicals. Re-determination of normal value, export price and dumping margin includes all aspects of such determination, including the issues of adjustment in freight, handling charges and customs duty.
29. As regards the argument that Authority in its Disclosure Statement has introduced word "CIF" for first time as the same was not appearing in the Final Findings, the Authority notes that this was precisely the reason the Appeal was filed by the responding exporter and the Tribunal has remanded back the proceeding to disclose the price adopted by the Designated Authority for 4-ADPA. The Authority has, therefore, clarified that the price adopted was CIF import price. As regards the argument of the domestic industry in this regard that the authority should adopt consumption price in India considering the CIF price and thereafter make appropriate adjustment, the Authority considers that when the CIF import price itself is available, there is no necessity of first adding various post importation expenses in India and then reducing the same. Since the authority is required to determine consumption price in Korea, the Authority has considered the CIF export price and made appropriate adjustments to arrive at the consumption price of Kumho Petrochemicals.
30. As regards the argument that the Authority is not required to review the completeness and correctness of the response to the questionnaire filed by KPC with regard to inland freight, the Authority notes that the scope of the post decisional hearing is re-determination of export price, normal value, and the dumping margin in so far as they relate to Kumho Petrochemicals. Re-determination of normal value, export price and dumping margin would include all aspects of such determination including issues of adjustment in freight, handling charges and customs duty.
31. As regards 4-ADPA prices from Germany being related party transaction, the Authority notes that the imports of 4-ADPA by Lanxess India from Lanxess Germany are between related companies situated in two different market economy countries and in the absence of any material evidence, it should be considered that these are at arm's length basis unless any evidence to the contrary is brought to the notice of the Authority.
32. As regards the argument that goods could have been cleared on a provisional assessment basis owing to several issues with regard to related party transactions in the instant case, the Authority notes that the interested parties have not provided any evidence to support their claim.
33. As regards the request for providing import price calculations in excel sheet, the Authority notes that there is neither any prescribed requirement under the law, nor it is established in the present case that the said information was imperative or in any way deficient to enable the exporter to offer its comments. The import listing provided by the domestic industry clearly shows very limited number of transactions, a number of which further fell in some price bands.
34. The Authority considers that appropriateness or otherwise of acceptance of 4ADPA consumption price reported by Kumho Petrochemicals Limited (erstwhile Korea Kumho Petrochemicals Ltd.) is beyond the scope of the present re-determination. The Authority notes that the CESTAT has upheld the decision of the Authority to reject 4-ADPA consumption price reported by KPC.
35. The domestic industry had contended that no disclosure had been made by the Authority concerning methodology adopted for constructing the cost of production of KPC, verification report, comments on the verification report offered by KPC which has formed the basis for the methodology adopted and determination of dumping margin and, therefore, information disclosed to the domestic industry is insufficient. The Authority holds that while remanding the matter back to the Designated Authority, the Tribunal has not given any such specific direction for disclosure of information demanded by the domestic industry. Recording of arguments of the interested parties is different from order of the Tribunal. The Tribunal has merely recorded the contention of the domestic industry raised at the time of hearing. The Tribunal has not passed any specific order with regard to disclosure of these

- documents. However, since the Tribunal has directed the Authority to make re-determination of the dumping margin, the Authority has appropriately disclosed the facts to all the interested parties in so far as these concern determination of dumping margin in respect of KPC. The Authority has disclosed adequately its determination with regard to computation of interest cost, steam cost, SGA expenses, valuation of captive inputs, expenses that should be added to the international price for determination of consumption price of 4ADPA.
36. As regards negative deduction in duty drawback, adjustment for freight difference and additions for other expenses, the Authority notes as follows:
- a. **Freight difference** - The consumption price of 4ADPA adopted by the Authority was based on CIF export price of 4ADPA from Germany to India. KPC has contended that the difference in freight in exports to India from Germany and exports to Korea RP from China should be adjusted. The exporter has, however, not quantified its claim in this regard. The Authority has accepted the argument of KPC, and has allowed this difference on the basis of best information available in this regard. The Authority while conducting the sunset review investigation concerning the same product had noted the argument of the KPC that expenses associated with import of the product vary with the distance involved. The Authority had appropriately adjusted the price for the difference in freight between freight from Germany to India and freight from China to Korea RP in that sunset review investigation (Final Findings Notification No 15/1/2013-DGAD Dated 29th April, 2014). The consumption price was, therefore, reduced by an amount of US\$ ***pmt, considering the same as the best available information with regard to difference in freight in view of no claim by KPC in this regard. Since KPC has not made any quantified claim, the Authority has adopted the same difference in the present case as well. The Authority notes that it is important to add/deduct following expenses for determining consumption price of KPC.
 - b. **Port expenses in Korea RP** - Since the 4ADPA price considered does not include port expenses and since imports of the product must involve port charges, the Authority has added ***% of the CIF import price as the port expenses in Korea. The Authority notes in this regard that KPC has not provided relevant information and, therefore, this amount has been adopted on the basis of best available information.
 - c. **Customs duty payable on imports in Korea RP**- Imports of 4-ADPA involves payment of ***% customs duty in Korea. Therefore, the same has been added to the CIF import price.
 - d. **Inland freight from port to factory** – The Authority notes that the exporter has not reported the expense that was incurred by the exporter in procurement of goods, shipment of the same from port to its factory. The consumption prices reported by the exporter did not contain separate breakdown for these expenses. The information with regard to freight incurred by the exporter in exporting the product from its factory to Indian sea port could not be considered in view of insufficient breakdown provided by the exporter in its questionnaire response. The Authority has considered appropriate to determine this expense at the rate of ***%. The Authority notes in this regard that the prescribed exporter questionnaire indeed requires the exporter to provide separate breakdown of inland transportation and overseas transportation. The exporter has, however, not provided the information in the form and manner prescribed.
 - e. As regards disallowance of the duty drawback adjustment, there is no straight jacket approach for allowing or disallowing this adjustment. The said adjustment is allowed after due verification of the claim of the producer/exporter on case to case basis. In case the producer/exporter is able to produce relevant documents in support of the said adjustment to the verification team, this adjustment is allowed. In the cases quoted by the applicant, the producer/exporter could not provide necessary documents showing details of import duty paid on raw materials used in the manufacture of subject goods and the duty drawback claimed and received on account of exports to India and other countries. It is further noted that in one of the cases quoted by the applicant, the duty drawback was allowed to another producer/exporter as the claim was duly supported with requisite documents to the satisfaction of the Authority. Since, this is a remand case and the Authority had already verified and allowed the adjustment at the time of original investigation after due verification, there is no merit in the contention of the domestic industry to disallow the adjustment on account of duty drawback at this stage.
37. The domestic industry has contended that the cost of production claimed by the exporter is understated. The domestic industry has further contended that such understatement may be on account of expenses that are required to be incurred in production of the goods in the form of steam, interest cost, SGA expenses, captive inputs, etc. The claim of the domestic industry has been examined in detail.
38. As regards the submission of KPC for the deduction of customs duty @15% from the price of 4ADPA adopted by the Authority, it is clarified that the Authority has considered only the CIF import price of 4ADPA and, therefore, custom duty was not included in the price adopted. Since the customs duty was not included, the same is not required to be excluded.
39. As regards the contention of KPC that the Authority would have already adjusted various expenses claimed by the domestic industry, it is clarified that the Authority had considered CIF import price in India and substituted the same with the consumption price reported by KPC. Therefore, the CIF import price in India is required to be

- adjusted for various expenses and thereafter, the consumption price is to be determined. The same has now been done.
40. As far as captive inputs are concerned, the Authority has adopted the claim made by the exporter on the basis of records maintained by the company.
 41. As regards the steam expenses, the Authority notes that the exporter is generating steam for consumption in various products. The exporter does not produce steam only for production of product under consideration. The expenses charged by the exporter on account of steam are on the basis of records maintained by the company. It is doing specific allocation of expense on steam and the same has been adopted for the present purpose.
 42. As regards SGA expense, the Authority has adopted turnover ratio for apportionment of SGA expenses.
 43. As regards the interest expenses, the Authority has considered the interest expenditure incurred by the company without adjusting the interest income. It is noted that the interest income earned by the company is for other business operations (i.e., financing operations) and, therefore, such interest income cannot be reduced from the interest expenses. The interest cost has, therefore, been re-determined without adjusting the interest income. The interest expense has been apportioned to various products on the basis of turnover.
 44. It has been contended that the Authority should have procured import data from its own sources and the information provided by domestic industry cannot be accepted. The Authority holds that neither at the time of original investigation, nor at the time of hearing before the Tribunal nor in the present post decisional hearing; the exporter, importer or any other interested party has provided any information which could be adopted for the present purpose. The Authority notes that while it is open for the interested party to advance arguments, they also hold an obligation to provide information which they consider relevant and appropriate.
 45. As regards the authenticity of information provided by IBIS, the Authority notes that the Authority has in several past investigations adopted information provided by the secondary source including IBIS for the purpose of determination of dumping, injury and causal link. IBIS is an independent private specialized agency and the information provided by IBIS is based on the information made available by the customs authorities. The Authority considers that the purpose of providing IBIS information was to determine the international price of the input. While there is no evidence to support of the contention that the claim of the domestic industry was not based on imports of 4ADPA into India, the Authority notes that in any case, the purpose of using this information is to arrive at a reasonable and representative international price of 4ADPA. None of the interested parties provided evidence to demonstrate that the possible exclusion or inclusion of a transaction has distorted the resultant price of US\$ *** adopted by the Authority for the purpose of present determination. The Authority also notes from the transaction wise details of imports of 4ADPA in India that the said information does not show significantly high or low price. On the contrary the said information shows a large number of transactions at one price. It is thus clarified that the Authority has adopted the 4ADPA international price after due verification.
 46. As regards the argument that the Authority should demonstrate that it has written to customs authorities at various ports, DGCI&S, Indian Embassies in the world to ascertain international price, it is clarified that it is not incumbent upon the Authority to seek information from various agencies as sought by KPC. Rule 6 lays down specific obligation with regard to the manner in which investigations should be conducted, the source from where information should be procured and the manner in which information should be processed and adopted. While the Authority is obliged to provide opportunity to the exporter, importer and users to provide relevant information, there is no legal mandate that Authority should write to various ports in the country or various Indian Embassies in the world or for that matter to DGCI&S to ascertain the international price. It is not the case that some interested party provided some evidence and the Authority ignored the same. The obligation to provide relevant information is with the domestic industry, exporters, importers and users and association of these parties.
 47. As regards the argument that the obligation to conduct the investigation is with the Authority and it not the prerogative of the domestic industry to partially conduct the investigation, the Authority clarifies that the Authority had conducted the original investigation and made the determination in terms of Anti-dumping Rules. The present re-determination has also been made by the Authority. Nothing has been left to the prerogative of either the domestic industry or for that matter any other interested parties.
 48. As regards the contention that the Authority has rejected information provided by private agencies in the past, the Authority notes that rejection or acceptance of information with regard to volume and value of imports is based on facts of a particular case. Merely because information provided by private agencies was found deficient and disregarded in some other investigation, it does not imply that information provided in the present case as well is also deficient and must be disregarded, or the source itself should be considered inappropriate forever. In fact, the Authority finds that the volume of imports reported by DGCI&S are sometimes lower than the volume of imports reported in secondary sources, while volume of imports reported in DGCI&S has also been found higher than the

volume of imports reported in secondary sources in some other cases. Moreover, in those matters, the issue involved is both volume and price of imports. Volume of import is relevant for the purpose of assessment of injury to the domestic industry and volume and value of imports is relevant for the purpose of determination of import price. The Authority, therefore, considers both volume and price of imports reported in the data provided by DGCI&S and private agencies. It is, therefore, highly important for that purpose that the import data adopted represents most exhaustive account of the imports of the product. However, for the present purpose, it is not necessary that the import data adopted represents most exhaustive account of 4ADPA. The important and relevant criterion is that the resultant import price of 4ADPA should be reasonable and representative of the international price of the product. It is also clarified that the import transactions considered for this purpose pertain only to the imports of 4ADPA and does not include any significantly high or low price.

49. As regards payment terms, the Authority does not consider the payment terms that were negotiated between the exporter and its raw material suppliers, nor it was established by any interested party that the payment terms in raw materials procurement were relevant factor. When payment terms and delivery terms were not contended as relevant parameters in respect of 4ADPA purchased by KPC from Sinorgchem, it cannot be contended that the payment terms and delivery terms between the supplier from Germany and buyer in India would be relevant for the present purpose.
50. As regards the adjustment for the difference in freight costs, it is clarified that since the price adopted by the Authority was CIF import price in India, the same has been appropriately adjusted for the difference in freight from China to Korea and the one from Germany to Korea.
51. The exporter and the importer have contended that the import transaction of 4ADPA adopted by the Authority could pertain to transaction between Lanxess Germany and Lanxess India and, therefore, the transaction value could be distorted because of the relationship. The Authority notes that it has not adopted the invoice value reported by either the exporter or the importer. The Authority notes that the customs authorities are required to satisfy themselves about the correctness of the assessable value reported by the related importer before considering them for assessment of customs duty. The Authority has adopted the transaction value considered by the customs authority for assessment of customs duty which is supposed to be distortion free due to relationship. In any case, the Authority notes that it has not been demonstrated by any party that the import price is in fact affected due to relationship.
52. As regards adoption of the import price from China, the Authority notes that adoption of import price from China is not open for the present re-determination. In any case, the import price from China could not be adopted for the very same reason for which consumption price of KPC was not adopted. If the consumption price of the exporter was rejected on the ground that the same was artificially low, the import price of 4ADPA of Chinese exporter in India cannot be adopted for the same reason. In this connection, the Authority notes that the domestic industry contended that Sinorgchem is holding capacities for 4ADPA significantly beyond its own requirement and was dumping the product under consideration by selling raw materials at artificially low prices.
53. As regards the argument that given the large quantities of 4ADPA that were being bought by KPC from Sinorgchem, there should be a volume discount on the consumption price, the Authority notes that KPC has not provided any evidence to demonstrate that a volume discount is invariably provided by the sellers when the quantities are large. It is not appropriate to generalize the proportion that the selling price would be lower if the volume is higher. In fact, it is quite possible that the selling price is lower despite lower volumes. In any case, it is a question of fact which should have been established by the interested parties.
54. As regards the issue of adoption of different exchange rates adopted, the Authority notes that there is no difference in the exchange rate adopted. The weighted average export rates are different due to the difference in associated volume as shown in the table below.

Particulars	Volume in Kg	Avg. Exch. Rate
China PR		
April-06	80,000	44.85
June-06	64,000	46.20
July-06	83,360	46.55
August-06	32,000	47.20
September-06	64,000	46.80
October-06	64,000	46.15

November-06	128,000	45.55
January-07	112,000	44.70
February-07	112,000	44.45
March-07	112,000	44.45
Total China PR	851,360	45.69
Germany		
April-06	241,100	44.85
May-06	108,380	45.35
June-06	154,820	46.20
July-06	109,100	46.55
August-06	44,160	47.20
September-06	44,260	46.80
October-06	88,500	46.15
November-06	89,820	45.55
December-06	133,220	44.95
January-07	109,540	44.70
February-07	66,320	44.45
March-07	43,840	44.45
Total Germany	1,233,060	45.60

55. As regards reasonable profit that should be adopted for the present purpose, the Authority has considered ***% of cost of sales excluding interest as profit as per its practice in the absence of any other information provided by the interested parties.
56. As regards the contention of KPC that the CESTAT upheld the decision of the Authority with regard to rejection of 4ADPA price on the assumption that there is a reliable international price in existence, the Authority holds that the argument of KPC is without any basis. In fact, the figure of US\$ *** adopted by the Authority and the basis of the same was acknowledged by the Tribunal. The observation of the Tribunal was that the said figure was not disclosed to the exporter, importer and other interested parties at the time of determination. The Tribunal has in fact directed the Authority to disclose the international price that had been adopted. This does not mean that the price of US\$ *** adopted by the Authority has been rejected by the Tribunal.
57. The Authority notes that the domestic industry had made available information with regard to international price of 4-ADPA on the basis of imports of the product from Germany to India in a number of its submissions. The domestic industry, in particular in their hearing paper book, post hearing written submissions and letters dated 6th February, 2008, has provided the transaction by transaction data of imports of 4-ADPA which formed the basis of the import price of US\$ *** per kg. These submissions made it abundantly clear that the claim of the domestic industry was based on the imports of 4-ADPA as per information procured by them from IBIS. The domestic industry has also provided non-confidential version of these submissions, which have been placed in public file. The interested parties, including Kumho Petrochemicals, had filed their rejoinder to the written submissions filed by the domestic industry and, therefore, had ample opportunity to comment on the correctness or otherwise of the IBIS data or the import price of US\$ *** per kg. as claimed by the domestic industry on the basis of imports of 4-ADPA in India. The Authority notes that while the interested parties could contend that they were not aware about the figure of US\$ *** adopted by the Authority or the source of the same, the interested parties cannot contend that they did not have opportunity to comment on the claim made by the domestic industry in this regard. It is also evident that the domestic industry had been disputing throughout the investigation the adoption of the cost of production of the Korean exporter and had been pleading consideration of import price into Korea and rejection of the cost of production of the exporter in view of inappropriateness of the procurement price. Kumho Petrochemicals and other interested parties, however, chose not to offer any comments on the amount of international price claimed by the domestic industry, nor offered any comments on the appropriateness of the source of information or accuracy of the information.
58. The Authority notes that the domestic industry in this remand proceeding has once again provided a statement showing imports of 4-ADPA into India as per information made available by IBIS, including transaction wise details of these imports of 4-ADPA in India. The Authority also notes that IBIS as a source of information for determination of import volume or import price has been used by the Authority in several investigations. The Authority notes that international price of 4-ADPA on the basis of imports of the 4ADPA from Germany to India as

US\$ *** per kg was adopted by the Authority at the time of original investigation. The Authority considered the arguments made by interested parties with regard to the appropriateness of IBIS data and does not find any infirmity with regard to adoption of 4ADPA price as US\$ *** per kg.

59. As regards contention that the Authority is not required to disclose individual costing elements of KPC to the domestic industry, the Authority notes that the rules require the Authority to address the issues and concerns raised by the interested parties while making determination. Since domestic industry has raised concerns with regard to specific elements of costing, the Authority is required to address the same. The Authority also notes in this regard that if an interested party raises specific concerns with regard to elements of cost or NIP of the domestic industry, the same are also considered and addressed by the Authority. The Authority, however, notes that the rules with regard to confidentiality are required to be followed in this regard and, therefore, while specific confidential information of the exporter cannot be disclosed, the Authority has addressed all the issues raised by the domestic industry with regard to cost of production of the exporter.
60. As regards the disclosure of verification reports prepared by the Authority and comments on the verification report and documents provided by the exporter or the domestic industry at the time of on the spot verification are concerned, the Authority notes that it is the consistent practice of the Authority not to disclose verification report to the domestic industry. The Authority also notes in this regard that verification reports are issued to the exporters in compliance with the WTO Agreement on anti dumping even though there is no such specific requirement under the Indian law.
61. As regards the contention that the exporter and importer did not comment on the claim of the domestic industry with regard to international price of 4ADPA, the Authority notes that non confidential submissions made by various interested parties were made available to the interested parties through the public file. These non confidential versions include submissions of the domestic industry with regard to their claim concerning international price of 4ADPA. The importer and exporter had clear opportunity to defend their interests and counter the claim made by the domestic industry. The exporter-importer however preferred not to offer any comments on the same or provide any other evidence of international price of 4ADPA. The main thrust of the arguments of the importer as well as the exporter was that the Authority cannot reject the consumption price reported by the exporter and its costs on the basis of the records maintained by the exporter.
62. Cost of production of KPC has been determined by considering the information provided by the exporter and verified by the Authority. All elements of expense and costs claimed by the exporters were allowed except for the following:
 - a. Consumption price of 4ADPA – The Authority has not accepted the consumption price of 4ADPA reported by the exporter. The Authority has adopted consumption price of 4ADPA as reported in IBIS data. The CIF price of US\$*** per kg has been adopted for the purpose. This has been adjusted for (a) the difference in freight between China and Korea and Germany and India; (b) port expenses in Korea; (c) customs duty on imports in Korea @ ***% and (d) inland freight in Korea from port to factory of KPC. The consumption price so adopted comes to US\$ *** per kg.
 - b. Interest cost – The interest expenses claimed by the exporter have been considered after excluding the interest income reported by the exporter. Interest cost has been allowed without adjusting interest income.
 - c. The cost of production/sales claimed by the exporter was *** KRW per Kg as against which the cost of production determined by the Authority is *** KRW per Kg. Full disclosure of cost of sales determined by the Authority was made to the exporter on confidential basis.
 - d. Since all sales made by the exporter were below the cost of sales determined by the Authority, the normal value has been determined on the basis of cost of sales after providing profits at ***% of cost of sales excluding interest.

D. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Dumping margin for Korea RP

i) Details of normal value determined for 6PPD for KKPC

63. The Authority has considered the cost of 4ADPA at the rate of US\$ *** per kg being the price at which the said raw material was sourced from a market economy country, i.e., Germany, based on the data provided by the domestic industry. The domestic industry vide their letter dated 6.2.2008 had attached a statement showing the above said price of US\$ *** per kg sourced from IBIS.
64. The Authority has adopted average exchange rate of *** KRW per US\$ and arrived at the rate for 4ADPA at *** KRW per Kg as against *** KRW per kg of 4ADPA claimed in Appendix-8B submitted by KKPC.

65. In view of the above, the cost of production of 6PPD has been reworked by revising the cost of 4DAPA from *** KRW per kg to *** KRW per kg. The other elements of cost with the exception of interest have been kept at the level claimed by KPC. As regards interest, the Authority has considered interest without adjusting interest income. This has resulted in increase in the cost of 6PPD from *** KRW per Kg to *** KRW per Kg.
66. Since the revised cost of *** KRW per kg of 6PPD, was higher than the domestic selling price for domestic sales of KKPC, the Ordinary Course of Trade Test had failed. The Authority had, therefore, considered the profit at ***% of cost of sales excluding interest to determine the normal value for 6PPD. The normal value so determined by the Authority works out to US\$ *** per Kg of 6PPD.

ii) Details of export price determined for 6PPD exported by KKPC to India

67. The Authority has determined the net export price based on the Appendix-2 filed by KKPC after due verification. The adjustments claimed by KKPC, viz., inland freight, ocean freight (inclusive of terminal handling charges, bill of lading fee, handling charges and wharfage), ocean insurance, bank charges and commission were verified and accepted. In addition, the negative adjustment for the duty drawback received on exports to India on the basis of revised customs duty considered on the 4ADPA price had been admitted. The net export price so determined by the Authority worked out to *** US\$ per Kg of 6PPD.

Dumping Margin For Kumho Petrochemicals Co, Ltd Korea RP

68. Dumping Margin based upon the above calculations of Normal Value and Export price has been worked out by the Authority in the table below.

Normal value US\$/Kg	Net Export Price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (%) Range
***	***	***	***	0 - 10

E. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

i) Injury Determination

69. The Authority considers that imports of PX13 during the POI increased significantly in absolute terms. Imports increased significantly in relation to total imports into India, production and consumption in India. With regard to the price effect, it is noted that imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market and selling price of the domestic industry declined significantly during POI. Performance of the domestic industry first improved and thereafter deteriorated in the POI in terms of production, capacity utilization, selling price, profits, cash profit and return on investments. Domestic sales and market share declined and the inventories increased throughout the injury period. Imports were suppressing domestic prices. The dumping margin determined in respect of imports from China PR and Korea RP was significant. Thus, the dumping of subject goods is causing injury to the domestic industry and that the domestic industry suffered material injury as a result of dumping of the subject goods.

Injury Margin Table

Injury Margin	UOM	POI
NIP	Rs./kg	***
Landed Value of Kumho Petrochemicals Co Ltd, Korea RP	Rs./kg	***
Injury Margin	Rs./kg	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin Range	%	20-30

ii) Conclusion on Causation

70. On the basis of the detailed examination done in the final findings vide Notification No.14/5/2007- DGAD dated 1st October, 2008 and the present determination, the Authority concludes that the subject goods were exported from the subject country at prices below their normal values resulting in dumping of the subject goods. Further, the landed price of imports was below Non Injurious Price of the domestic industry and the net sales realization of the subject goods of the applicants. Imports from subject countries caused material injury to the domestic industry establishing causal links between dumping of subject goods and injury to the domestic industry. Significant increase in the volume of dumped imports had resulted in significant decline in the market share of domestic industry. It was

further seen that decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from the subject country prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand. As a result, the sales of the domestic industry during the POI did not increase to such an extent that domestic industry could have optimally utilized its capacity. Consequently, production, sales and capacity utilization of the domestic industry suffered as a result of the decline in the market share of the domestic industry. Significant price undercutting caused by dumped imports prevented the domestic industry from increasing its prices. Resultantly, profit, cash flow and return on investment of the domestic industry deteriorated in the POI. Significant price undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment, these parameters deteriorated in POI after improving till 2005-06.

71. The Authority, therefore, concludes that the dumped imports originating in or exported from Korea and China had caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti-dumping Rules.
72. The Authority notes that the CESTAT vide its order dated 26.12.2014 had directed the Authority to re-determine normal value, export price and dumping margin in so far they relate to KPC and make modification to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing.
73. Having regard to final findings earlier notified, various submissions made by the interested parties during the course of the investigations as well as at the time of post decisional oral hearing and thereafter in their written and rejoinder submissions and considering the merits in the arguments raised by the interested parties in view of legal and factual position, the Authority holds that the final findings earlier notified by the Authority do not require any modification, except in respect of dumping margin, injury margin and quantum of anti dumping duty in so far as it relates to Korea Kumho Petrochemicals Ltd. The Authority holds that the product under consideration has been exported by Korea Kumho Petrochemicals Ltd., at a price below the associated normal value causing material injury to the domestic industry. The dumping margin so determined for Korea Kumho is above de-minimis. The Authority concludes that antidumping duties are therefore required to be imposed on the exports made by Korea Kumho Petrochemicals Ltd.

F. POST SECOND DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS

Post Second Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

74. The Authority notes that the post second disclosure statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the second Disclosure Statement. The important post second post Disclosure Statement submissions of the opposite interested parties, in brief, are as under:
 - a. Remand proceedings pursuant to the CESTAT order cannot exceed beyond its scope. The appeal of the Applicant Domestic Producer before the Hon'ble CESTAT was not allowed for any re-determination. The Applicant Domestic Producer was unable to indicate any sentence in the CESTAT Order which may demonstrate that any direction on the re-determination was given qua the appeal of the Applicant Domestic Producer.
 - b. The Designated Authority cannot review its own order and support new insertions and inventions of the Applicant Domestic Producer when it has no mandate to re-determine the aspect about the payment of customs duty and other such extraneous issues at this stage. The direction to re-determine means only the redetermination of all aspects which could not be done earlier due to non-disclosure of the prices of 4-ADPA used by the Designated Authority.
 - c. As far as KPC is concerned, in the appeal of KPC, it cannot be placed in the worse position on any issue than the position in which it already was before the filing of appeal on those issues. The issues as framed by the Hon'ble CESTAT highlight that the only issue regarding re-determination was that to disclose the proposed international price of 4ADPA to KPC and take into consideration any submissions made by KPC on the adoption of the same price. The issues to consider whether customs duty would have been paid on import of the 4ADPA and other expenses would have been incurred are not open for redetermination to the Designated Authority in the absence of remand on these issues.
 - d. It is submitted that the Applicant Domestic Producer as well as the Designated Authority were aware about the price of 4ADPA adopted. The Applicant Domestic Producer at no stage submitted that they were kept in dark about the prices used for substitution. Even the Applicant Domestic Producer supported the decision of the Designated Authority to full extent. Therefore, the Applicant Domestic Producer as well as the Designated Authority were aware about inclusion or exclusion of the customs duty or any other expense before use of such prices in arriving at the cost of production.
 - e. In such circumstances, it is but obvious a presumption that all such adjustments were already made which are now requested by the Applicant Domestic Producer. Further, even if it is assumed that it was not done by the Designated Authority and the Applicant Domestic Producer kept quite on such aspect and foregone its right by not challenging it in appeal, then the Designated Authority cannot now oblige the Applicant Domestic Producer

once again by accepting such adjustments. Once a right is forgone by the Applicant Domestic Producer, then such right cannot be resurrected in garb of the direction for redetermination in the appeal of the Respondents. The direction for redetermination is restricted in that manner.

- f. It is again reiterated that the word “CIF” in paragraph 27.c has been introduced intentionally though the same was not present earlier. Is it the admission that the Designated Authority did not care about the CIF price/FOB price, etc. in its determinations?
- g. CIF has been introduced to overcome the difficulty to make an addition of the customs duty in the claimed landed value once again to keep the dumping margin level.
- h. Further, when the Applicant Domestic Producer submitted the data for the last time, it would not have assumed that KPC has an operation in sea beyond the customs boundaries and, therefore, on the import of 4ADPA, customs duty would not have been payable. In other words, it is but obvious and beyond doubt that the Applicant Domestic Producer must have submitted the prices of 4ADPA for substitution after adding the customs duty payable in India at that time, i.e., 15%. The Applicant Domestic Producer as well as the Designated Authority failed to indicate any plausible reason because of that such adjustments were not done previously.
- i. Even if the Applicant Domestic Producer failed to include the customs duty at the point of time before the passing of the Final Findings dated 01.10.2008 and thereafter failed to file an appeal on the same aspect, it is not anymore open to the Applicant Domestic Producer to make a fresh claim before the Designated Authority to accept such claim.
- j. The Designated Authority had provided adjustment in relation to duty drawback while adopting the price of 4ADPA and, therefore, also it can reasonably be deduced that such adjustment was allowed if customs duty element was already included in the adopted price.
- k. The Applicant Domestic Producer has been blessed for all the adjustments sought even though such aspects were never raised and no appeal was filed on those aspects. The Respondents demonstrated from the Final Findings dated 01.10.2008 that it is an admitted position that price of 4ADPA to India by Sinorgchem was much higher than Price of 4ADPA to KPC. The reason for the difference was the quantity discount. The same difference should have been allowed as adjustment to the newly substituted price. However, it seems that Final Findings of the earlier Designated Authority on this fact has been ignored.

Post Second Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

75. The Authority notes that the post second disclosure statement submissions made by the Domestic Industry are repetitive in nature and have already been dealt with in the second Disclosure Statement. The important post second post Disclosure Statement submissions of the Domestic Industry, in brief, are as under:
 - a. The only scope of the present post decisional proceedings is to disclose the international price and methodology adopted for fixation of normal value, export price and dumping margin. Further the designated authority may re-determine normal value, export price and dumping margin in light of the CESTAT observation. The Designated Authority should not go beyond the directions of CESTAT.
 - b. The domestic industry requests the Designated Authority to disclose the methodology of determination of normal value in general and determination of interest cost, steam cost, SGA expenses and captive inputs in particular.
 - c. Domestic industry requests the Designated Authority to either add customs duties and all expenses associated with import in 4ADPA costs or disallow adjustment of negative deduction towards duty drawback.
 - d. Appropriately modify the dumping margin and consequently the duty quantum after making adjustments as requested by the domestic industry.

Examination by the Authority

76. The exporter's comments mainly relate to the scope of the Remand Investigation. The Tribunal passed the specific orders limiting the scope of the post decisional hearing to disclosure of international price of 4ADPA adopted by the Authority for re-determination 6PPD price, the export price, normal value and dumping margin in so far as they relate to Kumho Petrochemicals and disclose the methodology. The determination of revised Export Price, Normal Value and Dumping margin are in consonance with the said Order of the Tribunal. All the comments involve around re-determination of Export Price, Normal Value and Dumping Margin. The basis of redetermination has been amply described in the Final Findings. The calculations and methodology have been duly shared with the authorized representative of the Exporter. No specific comments have been made on the calculations. They have merely challenged the scope in which there are no merits.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

77. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
78. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

79. After examining the submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from Kumho Petrochemicals, Korea RP below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from Kumho Petrochemicals, Korea RP.
80. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from Kumho Petrochemicals, Korea RP in the form and manner described hereunder.
81. The Authority notes that the CESTAT had remanded the matter back to the Authority with a direction that the Authority shall re-determine for 6PPD the export price, normal value, and the dumping margin in so far as they relate to Kumho Petrochemicals, Korea RP. The Authority had recommended definitive anti dumping duty on the imports of Rubber Chemical 6-PPD (PX-13), originating in or exported from Kumho Petrochemicals, Korea RP vide its Final Findings Notification No.14/5/2007- DGAD dated 1st October, 2008, recommending imposition of the anti-dumping duty from the date of imposition of provisional findings Notification No. 14/5/2007-DGAD dated 28th February, 2008. The same was levied by the Central Government vide Notification No.133/2008-Customs dated 12th December, 2008 with effect from the Notification No 61/2008-Customs dated 5th May, 2008. In the remand case, the Authority has revised the Dumping Margin for Kumho Petrochemicals, Korea RP from what was recommended in the original Final Findings Notification No 14/5/2007- DGAD dated 1st October, 2008.
82. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends to the Central Government that in Column No.- 9, S. No 4, of the Duty Table in the Final Findings Notification No.14/5/2007- DGAD dated 1st October, 2008, the amount of duty may be amended to read as 5.90 as against 10.35 and further recommends to the Central Government that definitive antidumping duty as per the amount specified above may be imposed by the Central Government from 5th May, 2008, on all imports of the subject goods originating in or exported from Kumho Petrochemicals, Korea RP. The above mentioned amended duty will, however, have no effect on the amount of duty recommended by the Authority in its Mid Term Review Final Findings Notification No 15/21/2010-DGAD dated 5th August, 2011 including the Corrigendum dated 19th August, 2011 and the Sunset Review Final Findings Notification No.15/1/2013-DGAD dated 29th April, 2014.
83. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority